शर्मा हार्डवेयर
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in
हिंदी दैनिक
गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित
राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 27 | गुवाहाटी | शनिवार, 24 अगस्त, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

दसवीं और बारहवीं के लिए हो एक ही बोर्ड, केंद्र ने राज्यों को दी सलाह पेज 2
सर्किट हाउस का निर्माण कार्य 10 दिनों में होगा शुरू : मुख्यमंत्री पेज 3
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक किसी कीमत पर संसद से पारित नहीं होने... पेज 5
उम्मीद है कि कबड्डी 2036 ओलंपिक का हिस्सा होगा : पोलैंड कबड्डी महासंघ... पेज 7

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात

किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

असम-अरुणाचल सीमा पर छह क्विंटल सक्रिय बम बरामद

डुलुंग। पुलिस ने असम-अरुणाचल सीमा के पास डुलुंग में छह क्विंटल सक्रिय बम बरामद किए हैं। ये बम 25 साल पहले वायुसेना द्वारा किए गए परीक्षण अभ्यासों से अनजाने में छूट गए थे, जिन्हें मूल रूप से प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र में गिराया गया था। परीक्षण में क्रमश: 500 किलोग्राम और 100 किलोग्राम वजन वाले दो बम शामिल थे। 25 साल -शेष पृष्ठ दो पर

पाकिस्तान पहुंचा भारतीय सेना का ड्रोन मचा अफरा-तफरी

नई दिल्ली। भारतीय सेना का एक ड्रोन तकनीकी खराबी के कारण सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना शुक्रवार सुबह तकरीबन 9 बजे की है, जिसकी जानकारी खुद भारतीय सेना ने दी है। खबरों के अनुसार भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि सुबह 9.25 बजे, भारतीय क्षेत्र के भीतर प्रशिक्षण मिशन पर एक मिनी यूएवी ने -शेष पृष्ठ दो पर

नाबालिग के साथ गैंगरेप, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, आरोपियों को फांसी देने की मांग

नगांव (एजे / हि.स.)। कोलकाता और महाराष्ट्र के ठाणे में हुए दुष्कर्म को लेकर देशभर में बवाल अभी शांत नहीं हुआ है, इस बीच असम में भी एक ऐसे ही मामले को लेकर लोगों सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को असम में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए कथित गैंगरेप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि 3 लोगों ने मिलकर गुरुवार को नगांव के धिंग इलाके बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया है। एक ट्वीट में सीएम विश्व ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएंगे। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को साइट पर जाने और ऐसे राक्षसों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक, दुकानदारों ने अपने कारोबार बंद कर दिए, जबकि सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने अपराधियों के लिए कठोर दंड और महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। क्षेत्र में तनाव बरकरार है, जिसके कारण पुलिस गश्त और सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि नगांव के पुलिस अधीक्षक को शाम के समय गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, खासकर लड़कियों के शैक्षणिक संस्थानों और ट्यूशन केंद्रों के आसपास के इलाकों में। जिस अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया है, वहां के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि उसका इलाज मेडिसिन, सर्जरी और स्त्री रोग विभागों के चिकित्सकों की बहु विशेषज्ञता वाली एक टीम द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टरने कहा कि पीड़िता को भर्ती कराने के बाद, यौन अपराधों की जांच करने वाले दल ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। उधर प्रदर्शन में सबसे अधिक स्कूल एवं कॉलेज के बच्चे शामिल हुए। इस बीच, पुलिस ने घटना के सिलसिले में दो लोगों शाहिदुल इस्लाम और तफजुल इस्लाम को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) ने धिंग में बलात्कार की घटना के आरोपितों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर आज धिंग बंद का आह्वान किया था। आसू ने इस घटना की निंदा की। आसू के आह्वान पर आज धिंग में -शेष पृष्ठ दो पर

दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा : मुख्यमंत्री

नगांव। असम के नगांव जिले में तीन लोगों ने 14 साल की एक लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना धिंग इलाके में उस समय हुई जब लड़की गुरुवार शाम को ट्यूशन से घर लौट रही थी। नाबालिग को सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया और स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में तनाव फैल गया और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि, इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा -शेष पृष्ठ दो पर

डीजीपी ने शीघ्र न्याय का वादा किया

नगांव। नगांव जिले के धिंग में 14 वर्षीय लड़की के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के विचलित करने वाले मामले के मद्देनजर, असम के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीपी सिंह ने न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने की कसम खाई है। घटना के बाद धिंग के दौरे पर पहुंचे डीजीपी सिंह ने कहा कि पुलिस को घटना स्थल पर भेजकर गहन जांच की गई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि नाबालिग पीड़िता की पहचान छिपाने के लिए उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई है। सिंह ने कहा कि वे मामले में शामिल पुलिसकर्मियों से लगातार संपर्क में हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंह धिंग पहुंचे, -शेष पृष्ठ दो पर

मोदी-जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता

कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता से जुड़े चार समझौतों पर सहमति

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को कीव में व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच बातचीत का ज्यादातर हिस्सा द्विपक्षीय संबंधों पर केंद्रित रहा। दोनों देशों के बीच कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता से जुड़े चार समझौते भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कीव में उनके आधिकारिक आवास मरिंस्की पैलेस में वार्ता हुई। प्रधानमंत्री मोदी विशेष ट्रेन से यात्रा कर आज पौलेंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे वार्ता हुई। इसमें चर्चा का -शेष पृष्ठ दो पर

जेलेंस्की के साथ वार्ता में बोले प्रधानमंत्री मोदी-

रूस-यूक्रेन बिना समय गंवाए शुरू करें बात

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के दौरान शांति का संदेश दोहराते हुए कहा कि भारत रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के हर प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक में अपने संबोधन में कहा कि एक मित्र के रूप में शांति स्थापित करने में उनका कोई योगदान संभव है तो वे इसका निर्वहन करना चाहेंगे। दो वर्ष से अधिक समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष में तटस्थ नहीं था बल्कि वह शांति का पक्ष लेने वाला एक पक्षधर था। मोदी ने पिछले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी यूक्रेन युद्ध के संबंध में हुई चर्चा का उल्लेख किया और कहा कि समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। उन्होंने जेलेंस्की के साथ अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ *आंख में आंख* डालकर कहा कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं हो सकता। संघर्ष के बारे में मानवकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए उन्होंने दोनों पक्षों से आग्रह किया कि वे बातचीत के लिए आगे आएं। मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि -शेष पृष्ठ दो पर

बाढ़ : केंद्र ने त्रिपुरा में राहत कार्यों के लिए 40 करोड़ की राशि जारी की

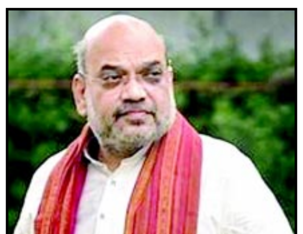

नई दिल्ली (हि.स.)। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 40 करोड़ रुपए अग्रिम रूप से जारी करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की। अमित शाह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ से केंद्रीय हिस्से के रूप में 40 करोड़ रुपए अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी है, ताकि प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जा सके। एनडीआरएफ की 11 टीमें, सेना की 3 टुकड़ियां और केंद्र द्वारा तैनात -शेष पृष्ठ दो पर

नदी में गिरी भारतीय पर्यटकों की बस, 27 शव बरामद

महाराष्ट्र के निवासी हैं सभी 40 यात्री, शवों को लेने भारत के केंद्रीय मंत्री आएंगी काठमांडू

काठमांडू (हि.स.)। गोरखपुर से नेपाल जा रही एक बस शुक्रवार को तनहूं के ऐनापहारा नामक स्थान से मार्स्यांगडी नदी में गिर गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 27 बस यात्रियों के शव बरामद किये हैं। हालांकि, नेपाल पुलिस ने बस में सवार सभी 40 यात्रियों, चालक और सहचालक की सूची जारी कर दी है लेकिन 14 मृतकों के नाम की शिनाख्त नहीं हो सकी है। घटनास्थल से 16 घायल लोगों को बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाली सेना का एक हेलीकॉप्टर मेडिकल टीम के साथ दुर्घटनास्थल पर रवाना किया गया है। कास्की पुलिस के प्रवक्ता और डीएसपी शैलेंद्र थापा ने बताया कि भारत के गोरखपुर से 40 यात्री दो दिन पहले ही बस (यूपी-53 एफटी 7623) से पोखरा आये थे। यह सभी लोग पोखरा के माझेरी रिसॉर्ट में रुके थे। वे बुधवार और गुरुवार को रिसॉर्ट में रुके और शुक्रवार सुबह काठमांडू जाने के लिए बस से रवाना हुए थे। शुक्रवार सुबह पोखरा से काठमांडू जा रही यह बस तनहूं के ऐनापहारा नामक स्थान से मार्स्यांगडी नदी में गिर गई। हादसा होने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और नदी के किनारे फंसी बस से यात्रियों -शेष पृष्ठ दो पर

केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें

सीबीआई को मिली केस चलाने की मंजूरी

नई दिल्ली। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है। सीबीआई ने इसकी जानकारी दी है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री -शेष पृष्ठ दो पर

उप्र : चल-अचल संपत्ति घोषित नहीं की तो 13 लाख कर्मचारियों की सैलरी पर संकट

नई दिल्ली (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी पर तलवार लटक रही है। राज्य के 17.58 लाख सरकारी कर्मचारियों में से सिर्फ 4.64 लाख कर्मचारियों को ही अगस्त महीने की सैलरी मिल सकती है। यानी राज्य के 13.23 लाख सरकारी कर्मचारी अगस्त महीने की सैलरी से वंचित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर ये संकट राज्य सरकार द्वारा पिछले साल अगस्त में जारी आदेश की वजह से आया है। इस आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी सरकारी पोर्टल पर देने का नियम बनाया गया था। इस आदेश के तहत 31 दिसंबर 2023 तक सारी जानकारी सरकारी पोर्टल मानव संपदा पर अपलोड की जानी थी। हालांकि इस समय सीमा का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार ने चल अचल संपत्ति की जानकारी देने की समय सीमा को और 6 महीने बढ़ते हुए 30 जून तक कर दिया। इसके बाद ये समय सीमा बढ़ा कर 31 जुलाई की गई। अंत में राज्य सरकार ने संपत्ति डिक्लेअर करने की अंतिम डेडलाइन 31 अगस्त तय कर दी। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 17.88 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 4.64 लाख सरकारी कर्मचारियों ने ही -शेष पृष्ठ दो पर

पुलिस पर डाकुओं का टूटा कहर रॉकेटों की बारिश से 11 की मौत

इस्लामाबाद। पुलिस पर पाकिस्तान के सबसे घातक डाकू हमले में मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, जबकि एक घायल अधिकारी की पंजाब के एक अस्पताल में मौत हो गई। रहीम यार खान जिले के काचा इलाके में गुरुवार को हुए इस हमले में आठ अन्य अधिकारी घायल हो गए। यह क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे अपने दस्यु ठिकानों के लिए कुख्यात है, जहां भारी हथियारों से लैस गिरोह अक्सर कानून प्रवर्तन से बचते हैं। पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने पुष्टि की कि पुलिस बलों ने हमले के पीछे माने जाने वाले कुख्यात दस्यु नेता बशीर शार को मार गिराया और पांच अन्य संदिग्धों को घायल कर दिया क्योंकि गिरोह के खिलाफ अभियान जारी है। अनवर ने कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी -शेष पृष्ठ दो पर

केंद्र ने 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध कहा- खतरनाक हो सकता है इनका इस्तेमाल

नई दिल्ली। सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 फिक्स्ड-डोज कांबिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाजार में अब ये दवाएं नहीं बिक सकेंगी। सरकार ने कहा कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। एफडीसी उन दवाओं को कहते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक दवाओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस समय बड़े स्तर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द की दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एसेक्लोफेनाक 50 एमजी + पैरासिटामोल 125 एमजी टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टारिन और कैफीन के संयोजन पर भी प्रतिबंध लगा -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact
97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE
Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc. ARTCLE WORLD, S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

दसवीं और बारहवीं के लिए हो एक ही बोर्ड, केंद्र ने राज्यों को दी सलाह

नई दिल्ली। राज्यों के साथ मिलकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटे केंद्र ने अब सभी राज्यों को दसवीं और बारहवीं के लिए एक ही स्कूली शिक्षा बोर्ड बनाने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों को यह सलाह तब दी है, जब अभी भी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम सहित देश के आठ राज्यों में दसवीं व बारहवीं के लिए अलग-अलग स्कूली शिक्षा बोर्ड मौजूद है। इतना ही नहीं, इनके परीक्षा व मूल्यांकन आदि का तरीका भी अलग-अलग ही है। हालांकि अब तक इन राज्यों में शामिल कर्नाटक ने केंद्र की सलाह को मानते हुए पिछले वर्ष ही अपने दसवीं और बारहवीं के सभी बोर्डों का आपस में विलय कर एक बोर्ड बना दिया है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि राज्यों में दसवीं और बारहवीं के एक शिक्षा बोर्ड होने से वह नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के विकास के लिए एक साझा रणनीति तैयार कर सकेंगे। जहां परीक्षा कराने से लेकर मूल्यांकन के एक जैसे मानक होंगे। अभी इन सभी राज्यों में दसवीं और बारहवीं के शिक्षा बोर्डों के काम-काज का तरीका एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। इसके चलते इन राज्यों में दसवीं और बारहवीं में छात्रों के प्रदर्शन में भारी अंतर भी देखने को मिलता है। फिलहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद शिक्षा मंत्रालय इन दिनों में राज्यों के साथ मिलकर शिक्षा में सुधार और एकरूपता लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में देश में कुल 59 स्कूली शिक्षा बोर्ड है। इनमें तीन राष्ट्रीय स्तर और 56 राज्य स्तरीय बोर्ड है। इनमें से 41 बोर्ड ऐसे है, जो दसवीं और बारहवीं के लिए कामन बोर्ड है। देश के जिन आठ राज्यों में दसवीं और बारहवीं के लिए अलग-अलग शिक्षा बोर्ड है, उनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, मणिपुर, तेलंगाना और बिहार शामिल है। इनमें बिहार में दसवीं के लिए अलग से एक संस्कृत बोर्ड है, जबकि असम में दसवीं और बारहवीं के लिए दो-दो बोर्ड है। वहीं केरल में भी बारहवीं के लिए दो बोर्ड है। ऐसे में कुल 18 बोर्ड ऐसे है, जो दसवीं और बारहवीं के लिए अलग-अलग संचालित होते है। इनमें दसवीं के नौ और बारहवीं के भी नौ बोर्ड है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय भले ही स्कूलों के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन देश के छह शिक्षा बोर्ड ऐसे है, जो अपने यहां एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते है। वह अपना खुद का पाठ्यक्रम अपने बोर्ड में पढ़ाते है।

पेंशन मामले में सिफारिशों को लागू नहीं करने पर एससी सख्त, मुख्य सचिवों को पेशी का आदेश

नई दिल्ली। अपने निर्देशों का पालन नहीं करने पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने उनसे यह बताने के लिए कहा है कि उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं देख सकता हूं कि कोई ठोस अनुपालन नहीं हुआ है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने पेश होना होगा या हम उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करेंगे। मामले की सुनवाई कर रही पीठ के अन्य न्यायाधीशों में जस्टिस जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, नगालैंड, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, बिहार, गोवा, हरियाणा और ओडिशा के शीर्ष नौकरशाहों को सुनवाई की अगली तारीख पर 27 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा। शीर्ष अदालत का यह निर्देश तब आया, जब न्याय मित्र के रूप में अदालत की सहायता कर रहे वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई बार आदेश जारी करने और समय दिए जाने के बावजूद 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आज तक एसएनजेपीसी की सिफारिशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है।

कट्टरपंथी जेहादियों के कारण असुरक्षित महिलाएं : अभाविप

गुवाहाटी (हिंस)। असम के कई हिस्सों में हाल ही में महिलाओं पर हुए अत्याचारों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), असम प्रदेश के आह्वान पर आज असम के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया गया। अभाविप की पहल पर आज गुवाहाटी के दिसपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने असम के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में हाल ही में वृद्धि के कारण असम की जनसांख्यिकी में बदलाव का हवाला देते हुए पूरे असम में विरोध प्रदर्शन किया। असम की इस भयावह स्थिति को देखते हुए उन्होंने असम सरकार से इस संबंध में बहुत तेजी से कार्रवाई करने और असम के लोगों से भी इस संबंध में जागरूक होने का आग्रह किया। प्रदर्शन में अभाविप के राज्य सचिव हेरल्ड महन ने कहा कि असम में महिला समाज कट्टरपंथी जिहादियों के कारण असुरक्षित है। नगांव, गुवाहाटी, लंका, सिलचर, ग्वालपाड़ा, धुबड़ी जिलों में विभिन्न स्थानों पर भी प्रदर्शन किया गया।

इंदौर : महू के पास निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से पांच मजदूरों की मौत

इंदौर (हि.स.)। इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत चोरल गांव में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से पांच मजदूरों की दबने से मौत हो मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात हुई, लेकिन शुक्रवार सुबह इसकी जानकारी लगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना को दुखद बताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से दो-दो लाख रुपए देने के निर्देश दिये। रेडक्रास के माध्यम से भी मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इस तरह मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करा दिया था। सभी संबंधित अधिकारी एवं एसडीआरएफ के दल को मौके पर तुरंत ही भेजा। बताया गया है कि यहां एक निर्माणाधीन फार्म हाउस में कल स्लैब डाली गई थी एवं रात में यहां कार्यरत मजदूर उसी के नीचे सो गए थे। स्लेब गिरने से उक्त मजदूरों की मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हितिका वासल, एसडीओपी उमाकांत चौधरी, एसडीएम चरणजीत सिंह हुड्डा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे एवं राहत तथा बचाव कार्य कराया। उन्होंने बताया कि मृतकों में पवन पांचाल (उम्र 35 साल) पुत्र भंवरलाल पांचाल निवासी बांसवाडा राजस्थान हाल मुकाम रुक सागर कालोनी इन्दौर, हरिओम (उम्र 22 साल) पुत्र रमेश मालवी निवासी ग्राम उन्मोद जिला शाजापुर, अजय (उम्र 20 साल) पुत्र रमेश मालवी निवासी जिला शाजापुर, राजा (उम्र 22 साल) पुत्र शेरसिंह निवासी इन्दौर तथा गोपाल (काका-उम्र 45 साल) पुत्र बाबुलाल प्रजापति निवासी छोटा बांगड़दा इन्दौर शामिल है।

नाजिरा में शव बरामद

शिवसागर (हिंस)। शिवसागर जिले के नाजिरा के बिहूबर में पुलिस ने आज एक शव बरामद किया। पुलिस ने बताया कि शव बिहूबर के रंगाजान रंगमंच पर बरामद हुआ। मृतक रात से ही लापता था। मृतक की पहचान बिहूबर के ओगुरिजान निवासी अल्ताब हुसैन के रूप में हुई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

भूपेंद्र हुड्डा से मिलीं पहलवान विनेश फोगाट, चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज

चंडीगढ़ (हिंस)। तय मानकों से अधिक भार होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हुई महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया है। पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद ही से विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि विनेश फोगाट ने अभी तक इस बारे में कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया है। पेरिस ओलंपिक से विनेश के बाहर होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा से मांग की थी कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। इस पर विनेश के ताऊ महावीर फोगाट तथा उनकी बेटी व भाजपा नेता बबीता फोगाट ने पलटवार किया था। विनेश की चचेरी बहन बबीता फोगाट पहले ही भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं।

GOVT OF ASSAM
INDUSTRIES, COMMERCE AND P. E. DEPARTMENT
NOTICE INVITING APPLICATION FOR PARTICIPATION IN INDIA INTERNATIONAL TRADE FAIR, 2024 AT PRAGATI MAIDAN, NEW DELHI.

Applications are invited from the interested Entrepreneurs/MSMEs for participation in the Assam Pavilion of India International Trade Fair, 2024 at Pragati Maidan, New Delhi to be held from 14th to 27th November, 2024. Prescribed Application Form may be collected from the Office of the GM, DICCs or downloaded from https://industriescom.assam.gov.in.

Last date of submission of completed application form to the office of the GM, DICC is 11th September, 2024.

-- Janasanyog /D/ 4654/24/24-Aug-24

Commissioner of Industries & Commerce, Assam
Udyog Bhawan, Bamunimaidam, Guwahati-21

पृष्ठ एक का शेष

नाबालिग के साथ...

बंद का व्यापक असर दिखा। धिंग में आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहने के साथ ही शहर में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से थमी रही। लोगों के आक्रोश को दिखते हुए धिंग में जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या पुलिस के साथ सीआरपीएफ की तैनाती की है। ऊपरी असम के शिवसागर जिले में भी धिंग रेप मामले के दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर खिलंजिया (स्थानीय) मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। खिलंजिया मुसलमानों ने घटना में शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ कामरूप जिले के नगरबेड़ा में छात्रों ने आज कोलकाता और नगांव के धिंग बलात्कार मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बिष्णु प्रसाद चालिहा कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने बैनर, पोस्टर आदि लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोपितों को उचित सजा देने की मांग की। इस बीच धिंग में सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में मोरीगांव जिले में हजारों पुरुषों, महिलाओं और युवा लड़कियों ने आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को गिरफ्तार करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी देने की मांग की। धिंग के साथ मोइराबारी बाजार में दुकानें और बाजार बंद रहे। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लोगों ने मोइराबाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने विभिन्न नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और लहरीघाट राजस्व सर्कल के सर्कल अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में पीड़िता के लिए न्याय की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बलात्कारियों का कोई धर्म नहीं होता। प्रदर्शनकारियों ने बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की।

दोषी को छोड़ा ...

एक्शन में आ गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जिन अपराधियों ने धिंग की एक हिंदू नाबालिका के साथ जघन्य अपराध करने का साहस किया, उन्हें कानून छोड़ेगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका को धिंग पहुंचने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शर्मा ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद कि एक विशेष समुदाय के सदस्यों का एक वर्ग बहुत सक्रिय हो गया है और उन्हें ऐसे अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हालांकि, हम अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद एक विशेष समुदाय अत्यंत सक्रिय हो रहा है। हिंदुओं को भाषाओं के आधार पर बांटने की कोशिश से सभी को सतर्क रहना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है। इस बीच, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार की सुबह सड़कों पर उतर आए। दुकानदारों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिरा दिए और सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने और महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की।

डीजीपी ने शीघ्र ...

जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जांच अधिकारियों से मामले पर चर्चा की। सिंह ने आश्वासन दिया कि हम त्वरित न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पहले ही एक गिरफ्तारी की है और संदिग्ध के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हम अपने मामले को और मजबूत करने के लिए मोबाइल डेटा सहित अतिरिक्त तकनीकी सहायता प्राप्त करने पर काम कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि जांच के लिए स्थानीय निवासियों और ग्रामीणों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। सिंह ने कहा कि हमारी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हम ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जियो-टैगिंग करेंगे और इलाके की सुरक्षा बढ़ाएंगे। सुरक्षा उपायों के तहत असम पुलिस शाम और रात के समय गश्त बढ़ाएगी। लड़कियों के स्कूलों के आस-पास के इलाकों और महत्वपूर्ण अंतर-समुदाय संपर्क वाले स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंह ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामागुड़ी, रुपोही, जुरिया और धिंग में सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। सिंह के दौरे में पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), पुलिस अधीक्षक (एसपी) नगांव और नगांव जिला आयुक्त के साथ चर्चा शामिल थी।

कृषि, चिकित्सा, संस्कृति...

एक महत्वपूर्ण हिस्सा द्विपक्षीय संबंधों को समर्पित रहा। इसमें व्यापार, आर्थिक विषय, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक 17 खेप, जिसमें से ज्यादातर चिकित्सा सामग्री है, यूक्रेन भेजी गई हैं। भारत ने आज यूक्रेन को चिकित्सा सहायता से जुड़ा भीष्म क्यूब सौंपा। उल्लेखनीय है कि भीष्म (भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री) क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक के उपचार के लिये तैयार किया गया है। यह एड क्यूब आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत का विचार है कि समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है। यूक्रेनी पक्ष वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन में भारत की निरंतर भागीदारी चाहता है। मोदी-जेलेंस्की की बातचीत कुछ हद तक सैन्य स्थिति और शांति के संभावित रास्तों पर केंद्रित रही है। विदेश मंत्री ने बताया कि वार्ता में दोनों नेताओं ने विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक संबंधों के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का काम अंतर-सरकारी आयोग को सौंपा है। इस वर्ष के अंत तक निश्चित रूप से आयोग की बैठक होगी। दोनों देशों के बीच आज कृषि एवं खाद्य उद्योग पर सहयोग, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता, वर्ष 2024-28 के लिए दोनों देशों के संस्कृति मंत्रालय के बीच सांस्कृतिक सहयोग और चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र पर करार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का यह पहला दौरा है। प्रधानमंत्री सुबह एक विशेष ट्रेन से पहुंचे और कीव रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के प्रथम उपविदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। वार्ता से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में महात्मा गांधी के शांति के संदेश की शाश्वत प्रासंगिकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। कीव में *ओएसिस ऑफ पीस* पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा मानवता के लिए आशा और शांति की किरण के रूप में कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में बच्चों पर मल्टीमीडिया मार्टिरोलॉजिस्ट प्रदर्शनी का दौरा किया। उनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति भी थे। संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों की याद में लगाई गई मार्मिक प्रदर्शनी से प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने युवा जिंदगियों कि अकाल मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया और सम्मान के रूप में उनकी स्मृति में एक खिलौना रखा।

बाढ़ : केंद्र ने त्रिपुरा ...

वायु सेना के 4 हेलीकॉप्टर पहले से ही राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, त्रिपुरा में हमारी बहनों और भाइयों को इस कठिन समय से लड़ने के लिए मोदी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मिलेगी। दरअसल, त्रिपुरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ आने से जानमाल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लगातार 48 घंटे से हो रही बारिश से त्रिपुरा के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। अबतक बाढ़ में बहने से 22 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह से बात कर राज्य को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है।

नदी में गिरी भारतीय ...

को निकालना शुरू किया। कास्की पुलिस प्रमुख एसपी मोहन थापा ने बताया कि दोपहर एक बजे तक 14 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 17 घायल लोगों को बचाकर अस्पताल भेजा गया है। तनहूं के डीएसपी दीपक कुमार राय ने कहा कि बचाव कार्य जारी रहने से मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। उनके मुताबिक बस में ड्राइवर और सह चालक समेत 43 लोग सवार थे। इनमें अनंत ओंकार इंगले (58), सीमा अनंत इंगले (45), सुहास राणे (49), सरला सुहास राणे (40), चंदना सुहास राणे (17),सुनील जगन्नाथ धांडे (62), नीलिमा सुनील धांडे (52), तुलसीराम तायड़े (64), सरला तुलसीराम तायड़े (58), आशा समाधान बविस्कर (52), रेखा प्रकाश सुखाड़े (40), प्रकाश नत्थू सुखाड़े (52), मंगला विलास राणे (53), सुधाकर कठीराम जावले (56), रोहिणी सुधाकर जावले (48),विजया करु जावले (59), भारती प्रकाश जावले (52), संदीप राजाराम सरोदे (52), पल्लवी संदीप सरोदे (42), गोकर्णी संदीप सरोदे (23), हेमराज राजाराम सरोदे (56), रूपाली हेमराज सरोदे (50), अनूप हेमराज सरोदे (25), गणेश पांडुरंग भारंबे (31), सुलभा पांडुरंग भारंबे (60), मिलन गणेश भारंबे (..), परी गणेश भारंबे (..), शारदा सुरेश पाटील (50), नीलिमा चंद्रकांत जावले (46), ज्ञानेश्वर नामदेव बोंडे (60), आशा ज्ञानेश्वर बोंडे (58), आशा पांडुरंग पाटील (63), सरोज मनोज भिरुड (54), पंकज भागवत भंगाले (42), वर्षा पंकज भंगाले (39), प्रवीण पांडुरंग पाटील (52), अविनाश भागवत पाटील (55), अनिता अविनाश पाटिल (44)हैं। इनके अलावा बस चालक मुर्तिजा और परिचालक रामजीत भी हैं। बस में सवार सभी पर्यटक महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। डीएसपी दीपक राय ने बताया कि भारतीय बस के 13 लापता यात्रियों को ढूंढने के लिए नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस के 10 गोताखोरों की टीम को नदी में उतारा गया है। बस नदी के किनारे फंसी हुई है। नेपाली सेना के प्रवक्ता गौरव केसी के मुताबिक सेना का हेलीकॉप्टर एमआई-17 मेडिकल टीम के साथ दुर्घटनास्थल पर रवाना किया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर आज सुबह दुर्घटना की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर +9779851107021 जारी किया है। उधर घायलों से मिलने और शवों को अपने साथ ले जाने के लिए कल सुबह भारत सरकार की युवा तथा खेलकूद राज्यमंत्री रक्षा खडसे काठमांडू पहुंचेंगी। वह पहले काठमांडू के अस्पताल में भर्ती घायलों से मिलेंगी। उसके बाद वह पोखरा जाकर शवों को अपने साथ लेकर विशेष विमान से जलगांव के लिए रवाना होंगी।

रूस-यूक्रेन बिना...

विचार-विमर्श और बातचीत से ही समस्या का समाधान संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस और यूक्रेन को एक-दूसरे को साथ बैठकर संकट से बाहर निकलने के लिए रास्ते तलाश करने होंगे। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की ओर संकेत करते हुए कहा कि विभिन्न देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध है। करीब सात घंटे की अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने बमबारी के शिकार बाल चिकित्सालय के समीप निर्मित स्मृति स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष में बच्चों की मौत से उनका मन भरा हुआ है। यह बहुत दुखद और हृदय विदारक है। मोदी ने संघर्ष के प्रारंभिक कालखंड में वहां भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में राष्ट्रपति जेलेंस्की की भूमिका की सराहना की तथा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर उन्हें शुभकामनाएं भी दीं।

सीबीआई को मिली...

अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने आबकारी मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ 29 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी। 12 अगस्त को चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उन्हें स्वीकृति नहीं मिली थी। कोर्ट ने इसके बाद मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए टाल दी थी। अब मंजूरी मिलने के बाद अदालत केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले पाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसे गुरुवार रात आठ बजे उन्हें सौंपा गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वो एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था। साथ ही उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा था। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को 5 अगस्त को वैध ठहराया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई यह साबित करने में सक्षम रही है कि केजरीवाल कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनके गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके थे। कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के मामले में नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था।

उप्र : चल-अचल...

अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी सरकारी पोर्टल पर दी है, जबकि 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। सरकारी आदेश में कहा गया था कि अगर आखिरी समय सीमा तक सरकारी कर्मचारी संपत्ति डिक्लेअर नहीं करते हैं तो न केवल उनकी सैलरी रोक दी जाएगी, बल्कि उनके प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि उसका इरादा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ ही जवाबदेही लाना और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को बढ़ावा देना है। इसीलिए अगस्त की सैलरी उन कर्मचारियों को ही दी जाएगी, जिन्होंने 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल में अपलोड कर दी होगी।

पुलिस पर डाकुओं ...

रहेगा जब तक प्रांत के प्रत्येक डाकू का सफाया नहीं हो जाता। डाकुओं ने पुलिस अधिकारियों पर घात लगाकर हमला करने के बाद बंदूकों और रॉकेट चालित ग्रेनेड का उपयोग करके हमला किया, जिनका वाहन बाढ़ वाले खेत में खराब हो गया था। हमलावरों ने अपने घातक मिशन को अंजाम देने के लिए अंधेरे का फायदा उठाया। इस अभूतपूर्व हमले की राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने निंदा की, जिन्होंने दुख व्यक्त किया और मारे गए अधिकारियों को शहीदों के रूप में सम्मानित किया। वरिष्ठ पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को शहीद अधिकारियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है।

केंद्र ने 156 दवाओं ...

दिया है। ट्रामाडोल दर्द निवारक दवा है। अधिसूचना के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया कि एफडीसी दवाओं का इस्तेमाल स्वास्थ्य के खतरनाक हो सकता है। जबकि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस मामले की जांच केंद्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने की गई थी। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) ने भी इन एफडीसी की जांच की और सिफारिश की कि इन एफडीसी का कोई औचित्य नहीं है। अधिसूचना में कहा गया है कि एफडीसी से खतरा हो सकता है। इसलिए जनहित में इन एफडीसी के निर्माण, बिक्री या वितरण पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इस सूची में कुछ ऐसी दवाएं शामिल हैं जिन्हें कई दवा निर्माताओं ने पहले ही बंद कर दिया है। पिछले साल जून में भी 14 एफडीसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। सरकार ने 2016 में 344 एफडीसी के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इस फैसले को दवा कंपियों ने अदालत में चुनौती दी थी।

असम-अरुणाचल सीमा...

पहले किए गए परीक्षणों के दौरान प्रायोगिक बमबारी की विरासत छोड़ने के बाद, ये बम इस क्षेत्र में एक प्रायोगिक गिराबट है। इनमें से एक बम 500 किलोग्राम वजन का है और दूसरा 100 किलोग्राम वजन का है।

पाकिस्तान पहुंचा भारतीय...

तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण खो दिया और हमारे भिंबर गली सेक्टर के सामने पाकिस्तान के नियंत्रण सेक्टर में बह गया। सेना ने बताया कि मीडिया इनपुट के मुताबिक पाक सैनिकों ने ड्रोन को बरामद कर लिया है। सेना ने कहा कि यूएवी को वापस करने के लिए पाकिस्तानी सेना को एक हॉटलाइन संदेश भेजा गया है।

सर्किट हाउस का निर्माण कार्य 10 दिनों में होगा शुरू : मुख्यमंत्री

चुनाव में किए गए वादों का अक्षरशः पालन करेंगे

हैलाकांदी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि चुनाव में हैलाकांदी की जनता से किए गए वादों का अक्षरशः पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह घोषणाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति का मुआयना करने के लिए यहां आए हैं। आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 दिनों के अंदर हैलाकांदी सर्किट हाउस के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय जिला आयुक्त को भूमि तलाश करने को कहा गया है, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले हैलाकांदी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पुस्तकालय के वर्तमान बिल्डिंग को पूरी तरह तोड़कर यहां अत्यधिक जिला पुस्तकालय बिल्डिंग वातानुकूलित ऑडिटोरियम के साथ बनाया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा की पांचग्राम में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को लेकर प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इसका काम आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री आज करीमगंज में भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि करीमगंज के हमारे मेहनती भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्हें अपार हर्ष हो रहा है, जिन्होंने लोकसभा चुनावों में हमारी पार्टी के लिए दो बार शानदार जीत सुनिश्चित की है।

धिंग बलात्कार घटना के आरोपियों को जल्द दी जाए कड़ी सजा : कांग्रेस

गुवाहाटी (हिंस)। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या की घटना से मर्माहत है। इस बीच असम के नगांव जिलांतर्गत धिंग में 10वीं पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हो गई। इसे लेकर लोगों में भारी रोष व्याप्त है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों को जल्द दंडित किए जाने की बात कही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले में बेहद सधी टिप्पणी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी के बेहद खास सांसद गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि धिंग में एक नाबालिग लड़की के साथ दुखदायी घटना हुई। मुझे उम्मीद है कि पुलिस और स्थानीय समुदाय मिलकर अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं इस दुख और पीड़ा की घड़ी में नाबालिग के माता-पिता के साथ खड़ा हूं। घटना को लेकर नगांव लोकसभा के कांग्रेस सांसद एवं असम सरकार के पूर्व मंत्री प्रद्युत बरदलोई ने भी एक पोस्ट करते हुए कहा है कि दोषियों की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। चाहे कोलकाता के उस युवा डॉक्टर का मामला हो या मेरे लोकसभा क्षेत्र के धिंग के स्कूली बच्चे का। ऐसे कुकर्म किसी भी समाज को किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकते। मैं यह भी मांग करता हूं कि दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा है कि असम पुलिस को जिम्मेदारी लेनी होगी और जनता को भी कड़ी नजर रखनी चाहिए ताकि धिंग में बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं में शामिल अपराधी किसी भी कारण से बच न सकें। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ऐसी सजा दी जाए ताकि कोई भी ऐसी घटनाओं को दोहराने की हिम्मत न करे। छात्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए संकट के इस समय में पीड़ित परिवार के धैर्य और साहस को बढ़ाने की कामना करता हूं!

जनसंपर्क के जरिए भाजपा का सदस्यता अभियान

गुवाहाटी (हिंस)। भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में 1 सितंबर से शुरू किए जा रहे सदस्यता अभियान के लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। आज जोरहाट, दक्षिण कामरूप, गुवाहाटी, पूर्वी कार्बी आंग्लांग और पश्चिमी कार्बी आंग्लांग में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। दक्षिण कामरूप जिले के कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और प्रदेश भाजपा महासचिव पल्लव लोचन दास ने पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों के लोगों से संपर्क के जरिए भाजपा के सदस्यता अभियान के इस महान कार्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर, यह कार्यशाला गुवाहाटी महानगर जिला के हेंगराबाड़ी में आयोजित की गई। प्रदेश प्रवक्ता किशोर उपाध्याय इसमें मौजूद थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरे अभियान के बारे में विस्तार से बताया। बैठक में प्रदेश भाजपा के संगठन महासचिव आर रवींद्र राजू, गुवाहाटी की पूर्व सांसद क्वीन ओजा और दिसपुर के विधायक अतुल बोरा सहित अन्य कई लोग शामिल हुए। कार्यशाला में प्रदेश महासचिव डिप्लू रंजन शर्मा भी शामिल हुए। जोरहाट जिले में प्रदेश प्रवक्ता पंकज बरबरा, पूर्वी कार्बी आंग्लांग जिले में प्रदेश प्रवक्ता रंजीब कुमार शर्मा और पश्चिमी कार्बी आंग्लांग जिले में प्रदेश कार्यालय सचिव सुशांत विश्वास इसमें मौजूद रहे। जिला स्तरीय प्रशिक्षण अगले दो दिनों तक जारी रहेगा। जिला प्रशिक्षण के बाद जोनल स्तर के प्रशिक्षण और जोनल प्रशिक्षण के बाद बूथ स्तर के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे।

मोरीगांव में ड्रग्स माफिया परिवार को ग्रामीणों ने समाज से किया बहिष्कृत

मोरीगांव (हिंस)। मोरीगांव के देशी मुस्लिमों ने मोरीगांव के कुख्यात ड्रग्स माफिया टूटो उर्फ रशीमुद्दीन अहमद को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति द्वारा लिये गये इस फैसले के बाद अब उसका परिवार समाज में कहीं आवाजाही नहीं कर सकेगा। स्थानीय लोगों ने मोरीगांव पुलिस प्रशासन की भूमिका को लेकर भी नाराजगी जताई है। लोगों ने आखिरकार खुद ही कार्रवाई करने का मन बनाया। वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी ने टूटों के परिवार को समाज से बहिष्कृत करने के साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कब्र खोदने की जगह नहीं देने का भी एलान किया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले लोगों ने टूटू के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोरीगांव सदर थाने में धरना भी दिया था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि, टूटू नामक यह कुख्यात ड्रग्स तस्कर मोरीगांव पुलिस के आला अधिकारियों का खास होने का दावा करते हुए गांव के लोगों के सामने सरेआम कारोबार चला रहा है। पुलिस पर आरोप है कि टूटू के मामले में वे ढिलाई बरतते हैं।

नगांव में हेरोइन के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिंस)। नगांव पुलिस ने हेरोइन के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज बताया कि एसआई अच्युत फूकन के नेतृत्व में नगांव पुलिस की टीम ने कचुवा से संदिग्ध हेरोइन से भरे दो साबुनदानी बरामद किए, जिनका वजन 24.88 ग्राम था। आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

कोलकाता और नागांव में हुई बलात्कार की घटना को लेकर नगरबेड़ा में विद्यार्थियों का प्रदर्शन

नगरबेड़ा (विभास)। कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर मौमिता देबनाथ के बलात्कार और हत्या और नगांव के धींग की 10वीं कक्षा की छात्रा के सामूहिक बलात्कार के विरोध में आज कामरूप जिले के बोको छयगांव निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नगरबेरा में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिमला प्रसाद चालिहा कॉलेज, नगरबेरा से नगरबेड़ा बाजार के बीच में यहां छात्रों ने विशाल विरोध रैली निकाली। विरोध मार्च में भाग लेने वाले छात्र बलात्कारियों को फांसी दे, महिलाओं का उत्पीड़न बंद करे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे, तरह-तरह के नारे लगाकर माहौल तनावपूर्ण बना देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व शर्मा और पुलिस प्रशासन को राज्य में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें फास्ट-टेक अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए और दोषियों को फांसी पर लटकाना चाहिए।

मिजोरम : भैरबी-होरटोकी के बीच नवनिर्मित रेललाइन पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, सीआरएस ने दी परिचालन की मंजूरी

गुवाहाटी (हिंस)। रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) सुमित सिंघल ने 22 अगस्त को भैरबी और होरटोकी के बीच 16.725 किमी नई बीजी रेललाइन पर माल और यात्री ट्रेनों के परिचालन शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी। इससे पहले सीआरएस ने बीते महीने के अंत में उक्त सेक्शन का निरीक्षण किया था। इस नई रेलवे लाइन पर अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेनों का परिचालन किया जा सकेगा। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पूसीरे) के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने शुक्रवार को बताया है कि भैरबी और होरटोकी के बीच नवनिर्मित बीजी लाइन सेक्शन में 20 बड़े पुल और 27 छोटे पुल हैं और इसमें तीन रोड ओवरब्रिज और एक रोड अंडरब्रिज भी शामिल हैं। इस नए सेक्शन में 13 सुरंग व कवर्ड मार्ग हैं। इस इलाके में औसत वार्षिक 2112. 823 मिमी बारिश होती है। साथ ही यह सेक्शन भूकंपीय क्षेत्र पांच में आता है। मुख्य लाइन में अधिकतम 100 किमी प्रति घंटे और लूप लाइनों में 30 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेन संचालन के लिए इस सेक्शन का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सेक्शन वर्तमान में चल रही 51.38 किमी लंबी भैरबी-साईरंग नई रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है। सफल निरीक्षण और स्पीड ट्रायल के बाद सीआरएस ने बिछाई गई नई रेलवे लाइन पर अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे की गति से ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी है। बिछाई गई यह नई लाइन इस मार्ग से और अधिक माल एवं यात्री परिवहन में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि इस सेक्शन में कुल 27.03 प्रतिशत कर्वड ट्रैक है। पूरे सेक्शन में समपार फाटक नहीं है। सेक्शन को एमएसीएल सिग्नल सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान किया गया है। होरटोकी रेलवे स्टेशन पर नया फुट ओवरब्रिज, द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय, कवर्ड प्लेटफॉर्म्स, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना पूरी होने पर कुल 51.38 किमी लंबी भैरबी-साईरंग नई रेल परियोजना मिजोरम के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, क्षेत्र में लघु उद्योगों को विकसित करने में मदद करेगी और राज्य के पर्यटन को बढ़ावा प्रदान करेगी। इसके ट्रैक पर सुरंगों की कुल लंबाई 12853 मीटर है। परियोजना में कुल 55 बड़े पुल और 89 छोटे पुल होंगे। साईरंग स्टेशन के पहुंच पर पुल संख्या 196 के स्तंभ पी-4 का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है, जो परियोजना का सबसे ऊंचा स्तंभ है।

टेक्नीश 2024 : आईआईटी गुवाहाटी के प्रीमियर टेक्नो-मैनेजमेंट फेस्ट की वापसी

गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने गर्व के साथ 29 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले अपने वार्षिक तकनीकी-प्रबंधन उत्सव टेक्नीश 2024 की घोषणा की है, जो नवाचार, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले कुछ वर्षों में, टेक्नीश देश भर से कुछ सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को एक साथ लाने वाले एक प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है, और इस साल भी यह परंपरा नए उत्साह के साथ जारी है। टेक्नीश 2024 में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईएसबी और अन्य प्रसिद्ध क्षेत्रीय कॉलेजों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिभागी भाग लेंगे। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के छात्र नवाचार और तकनीकी विशेषज्ञता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। उल्लेखनीय प्रतियोगिताओं में रोबोवार्स और एक्वावार्स शामिल हैं, जिसमें क्रमशः इंजीनियरिंग की सरलता का प्रदर्शन किया जाएगा और प्रतिभागी पानी के नीचे रोबोटिक्स का संचालन करेंगे। प्रतियोगिता से परे, टेक्नीश 2024 में नेक्सस और लेक्चर सीरीज की सुविधा होगी, जहां विभिन्न उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के विशिष्ट वक्ता छात्रों की शैक्षिक यात्रा को समृद्ध करते हुए अमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। समाज में योगदान देने के अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए, टीम टेक्नीश ने प्रतिष्ठित प्रायोजकों के समर्थन से सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन पहलों में ब्रह्मपुत्र नदी की सफाई अभियान, वंचित क्षेत्रों में हैंड वॉश और सैनिटाइजर का वितरण, लड़कियों के स्कूलों में सैनिटरी पैड अभियान, आईआईटी गुवाहाटी परिसर में रक्तदान शिविर और संस्थान में एक निःशुल्क दंत चिकित्सा जांच शिविर शामिल हैं। ये प्रयास प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से परे सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए टेक्नीच की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। टेक्नीश 2024 में बॉलीवुड नाइट और कॉमेडी नाइट सहित मनोरंजन के कई विकल्प भी पेश किए जाएंगे, जिससे प्रतिभागियों को प्रतियोगिताओं से कुछ समय का ब्रेक मिलेगा। इसके अलावा, इस साल के उत्सव में लेगेसी नामक एक ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता भी पेश की गई है, जो प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों को आकर्षित करने का वादा करती है। फास्टएक्स, लाइव एक्सट्रीम द्वारा प्रस्तुत, लर्नहिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से, टेक्नीश 2024 छात्रों को वेबसाइट पर कार्यशालाओं और नेक्सस के लिए पंजीकरण करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रतिभागियों को यहां प्रोनाइट, प्रदर्शनियों और अन्य उत्सव आकर्षणों का लुफ्त उठाने का भी मौका मिलेगा। टेक्नीश 2024 के संयोजक सम्यक शर्मा ने कहा कि 3 दिन और 4 रातों तक चलने वाला टेक्नीश तकनीकी और प्रबंधकीय दुनिया का एक आदर्श संयोजन है। अपनी वेबसाइट पर 50, 000 लोगों की उपस्थिति और 50 लाख से अधिक हिट्स के साथ, इसने रोबोटिक्स से लेकर कंसल्टेंसी, लेक्चर, इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, वर्कशॉप, मैराथन आदि जैसी पहलों, प्रतियोगिताओं के साथ 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। टेक्नीश ने उत्तर पूर्व भारत और देश भर में प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ नवोदित प्रतिभाओं की दुनिया और उद्योग जगत के बीच एक सेतु के रूप में काम करके एक बड़ा प्रभाव डाला है। टेक्नीश 2024 से नजदीकी बढ़ने के साथ, आईआईटी गुवाहाटी नवाचार और सामाजिक बेहतरी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहा है। हम इस अविस्मरणीय उत्सव में सभी का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।

होजाई : महेश्वरी व दायमा परिवारों ने मनाया सातुड़ी तीज का त्यौहार

होजाई (निसं)। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होजाई में कजली तीजका त्यौहार दायमा व महेश्वरी परिवारों ने हर्षोल्लास के साथ बृहस्पतिवार सांय को मनाया। भादो महीने में मनाए जाने वाले इस त्यौहार को सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। सदियों से चले आ रहे इस त्यौहार की विशेषता धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। इसमें परिवार के सभी सदस्यों के सुख, समृद्धि के साथ-साथ गांव देश में खुशहाली हेतु पूजा की जाती है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सुशील राठी व प्रतिभा राठी ने बताया त्यौहार में नीम के वृक्ष का सबसे बड़ा महत्व है। पर्यावरण के लिए वृक्षों की अपनी भूमिका रहती है। इसीलिए नीम का वृक्ष को इसमें महत्व दिया गया है। पूजन हेतु चना, चावल, गेहूं अच्छी तरह से सिकाई कर उसका आटा बनाया जाता है एवं शुद्ध घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। इसमें स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। इस त्यौहार के दिन महिलाएं

पूरे दिन निराहार रहती हैं। संध्या काल में कई घरों की महिलाएं एकत्रित होकर नीम वृक्ष की डाली को मिट्टी की तलाई बनाकर उसे रोप कर पूजा करती हैं। महिलाएं लाल पीली साड़ी पहने हाथों में मेहंदी लगाए अपने-अपने घरों से पूजन सामग्री के अलावा फल जिसमें आम, अनारस, नींबू, अमरुद, नाशपति आदि लेकर पूजा स्थान पर पहुंची। तत्पश्चात महिलाओं ने पूजन प्रारंभ किया इसमें दूध का विशेष महत्व है। नीम की डाली लगी तलाई को पानी व दूध से भर दिया जाता है।

एसएसबी के 24वें बटालियन, रंगिया ने विद्यार्थियों संग चलाया पौधरोपण कार्यक्रम

रंगिया (विभास)। 24वें बटालियन के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के कमांडेंट दीपक सिंह, के मार्ग-दर्शन में एसएसबी रंगिया द्वारा निरंतर चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत रंगिया की सीमा चौकी पहाड़पुर एवं नालापाड़ा द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों व स्थानीय जनता के साथ मिलकर हारीनचारा एलपी स्कूल व प्रार्थमिक विद्यालय बोरंगाजुली नं-01 में पौधारोपण किया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान, सीमा चौकी पहाड़पुर ने-125, व सीमा चौकी नालापाड़ा द्वारा 100 कुल 225 पौधों को लगाया गया। इस अवसर पर श्री दीपक सिंह, कमांडेंट, 24वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल रंगिया (असम)द्वारा बल के सभी कार्मिको एवं स्थानीय जनता को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होने कहा कि वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है क्योंकि पेड़ पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करते है और हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते है। यदि अधिक पेड़ लगाये जाए तो पर्यावरण को मानव जीवन के लिए एक अधिक सुरक्षित स्थान बनाया जा सकता है। वृक्ष प्रदूषण को भी कम करता है जो हमारे स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन के लिए अत्याधिक लाभप्रद साबित होता है। वर्तमान में जगंलो में वृक्षो की अत्याधिक कटाई व उद्योगो के कचरे व वाहनों के अत्याधिक प्रदुषण फैलाने से हमारा पर्यावरण दिन-प्रतिदिन प्रदुषित होता जा रहा है। जिससे आम जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। पेड़ लगाकर हम अपने गृह को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रवाभों से बचा सकते है। इसलिए उन्होने ने सभी से आग्रह किया कि पर्यावरण को बचाने हेतु हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाना होगा और हम अपने दैनिक जीवन मे हर संभव बदलाव लायेगें एवं अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे।

No.DDB/BTC/SOPD/NIT-04/2024-25/440 *Date 23/08/2024*

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders are invited with affixing non refundable court fee stamp of Rs. 8.25 (Rupees Eight and Paise Twenty Five) only by the undersigned from the intending Contractors/Suppliers/Firms for the works mentioned below under SOPD fund P&RD Deptt. for the year 2024-25.

Sl. No.	Name of Work	(Approx.) Tender Value (Rs. In Lakh)	EMD/Bid Security (in Rs. 1% ST, SC & 2% Oth)	Cost of Tender Paper	Time of Completion (Month)	Pre-bid Date & Time	Last date & Time of Bid submission	Date & Time of Bid Opening.)
1	Imp. of Molandubi-Marupara road with E/F & S/G at Molandubi.	Rs. 13,86,273/-	Rs. 14,000.00	Rs.420/-	3 Months	09.09.2024 (10.30 A.M)	16.09.2024 (02.00 P.M.)	16.09.2024 (02.30 P.M.)
2	Const. of RCC Box Culvert at Genduguri Near ED Resident.	Rs. 14,86,842/-	Rs. 15,000.00	Rs.450/-	3 Months	09.09.2024 (10.30 A.M)	16.09.2024 (02.00 P.M.)	16.09.2024 (02.30 P.M.)
3	Const. of E/F and S/G at Maoriagaon Village from PWD Road to Jakisan House.	Rs. 13,86,272/-	Rs. 14,000.00	Rs.420/-	3 Months	09.09.2024 (10.30 A.M)	16.09.2024 (02.00 P.M.)	16.09.2024 (02.30 P.M.)
4	Rep/Renovation of Dotma Dev. Block staff Quarter at Dotma.	Rs. 14,28,576/-	Rs. 15,000.00	Rs.450/-	4 Months	09.09.2024 (10.30 A.M)	16.09.2024 (02.00 P.M.)	16.09.2024 (02.30 P.M.)

Details NIT may be seen in all working days during office hours in the office of the undersigned. Tender Papers will be issued to the contractors or their authorized agent from 28-08-2024 to 13-09-2024 in the office of the undersigned on payment of cost of Tender paper in the form of demand draft /Bankers Cheque from any Nationalized Bank, duly pledged in favour of the Principal Secretary, BTC, Kokrajhar, Payable at Kokrajhar.

Sd/-
Block Development Officer,
Dotma Dev. Block, Dotma

IPR(BTC)/C/2024-25/379

संपादकीय

आरक्षण पर 'भारत बंद'

आरक्षण पर 'भारत बंद' का आह्वान...! सफल रहा या बेअसर साबित हुआ, यह अलग मुद्दा है, लेकिन दलित-आदिवासी संगठनों ने 'भारत बंद' का आह्वान क्यों किया? यह आश्चर्यजनक लगा। क्या ऐसी नकारात्मक और विध्वंसक राजनीति भी बाबा अंबेडकर की देन है? क्या सर्वोच्च अदालत की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भी सामूहिक, सड़किया विरोध करना अंबेडकर की सीख है? क्या बाबा के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में यह उल्लेख नहीं है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या संविधान पीठ ने विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोटे के भीतर कोटे की व्यवस्था भी संवैधानिक है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के परिसर में सांसदों के एक समूह को सार्वजनिक तौर पर आश्वस्त नहीं किया था कि आरक्षण में उप वर्गीकरण के न्यायिक फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा? संविधान पीठ के फैसले का किसी सरकार द्वारा ऐसा विरोध भी आश्चर्यजनक है। अलबत्ता संसद के पास ऐसी संवैधानिक शक्तियां हैं कि वह संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर सकती है। दलित और आदिवासी संगठनों को क्या आशंका थी कि उन्होंने 'भारत बंद' का आह्वान किया और देश के कुछ हिस्सों में अराजकता फैलाई। उनका आरक्षण सुनिश्चित है। संविधान पीठ ने जिस क्रीमीलेयर की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने फिलहाल उसे भी अस्वीकार कर दिया है। दलित और आदिवासियों को सुनिश्चित कौन कर सकता है? क्या कांग्रेस, सपा, राजद, बसपा सरीखी राजनीतिक पार्टियां दलितों और आदिवासियों को बुनियादी तौर पर विश्वास दिला सकती हैं? बहरहाल नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं। यह उनका मौलिक अधिकार-सा बन गया है। यह दीगर है कि भारत सरकार के कुछ शीर्ष और उच्च पदों पर उनकी भागीदारी 4 फीसदी और 4.5 फीसदी है। यह परंपरागत विसंगतियों का ही नतीजा है। 2014 में भारतीय सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार शासन में आई थी। सत्ता के 10 सालों में आरक्षण-विरोधी अथवा दलित, आदिवासी-विरोधी एक भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया। पहली बार देश के राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला को आसीन कराया गया। अभी 45 उच्च पदों पर जो सीधी नियुक्तियां की जानी थी, उस फैसले को भी वापस ले लिया गया। विपक्ष कुछ भी व्याख्या करता रहे। बेशक भाजपा की तुलना 'विषैले सांप' से करता रहे। सवाल है कि दलित, आदिवासी संगठनों को कोई ठोस शिकायत है अथवा वे राजनीतिक नेरेटिव से संचालित किए जा रहे हैं? जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वे आरक्षण, संविधान बचाने के मुद्दे पर मोदी और भाजपा का राजनीतिक विस्तार रोक सकते हैं, वे 'भारत बंद' के दौरान कहां थे? सडक़ पर मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरीखे नेता दिखाई नहीं दिए, जो आजकल दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के पैरोकार बने हैं। यदि संगठनों को संविधान पीठ के फैसले पर आपत्ति थी, तो वे सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते थे। संविधान पीठ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, जिसके खिलाफ 'भारत बंद' के जरिए विरोध-प्रदर्शन किया जाए। वह न्याय का सर्वोच्च और अंतिम मंच है। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि 'भारत बंद' का आह्वान किया जाता। पंजाब और हरियाणा में कुछ दलित जातियां ऐसी हैं, जिन्होंने 'भारत बंद' का समर्थन नहीं किया। वाल्मीकि और मजहबी सिख आदि आरक्षण के उप वर्गीकरण के पक्षधर हैं।

दलित-आदिवासी संगठनों ने 'भारत बंद' का आह्वान क्यों किया? यह आश्चर्यजनक लगा। क्या ऐसी नकारात्मक और विध्वंसक राजनीति भी बाबा अंबेडकर की देन है? क्या सर्वोच्च अदालत की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भी सामूहिक, सड़किया विरोध करना अंबेडकर की सीख है? क्या बाबा के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में यह उल्लेख नहीं है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या संविधान पीठ ने विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोटे के भीतर कोटे की व्यवस्था भी संवैधानिक है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के परिसर में सांसदों के एक समूह को सार्वजनिक तौर पर आश्वस्त नहीं किया था कि आरक्षण में उप वर्गीकरण के न्यायिक फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा? संविधान पीठ के फैसले का किसी सरकार द्वारा ऐसा विरोध भी आश्चर्यजनक है। अलबत्ता संसद के पास ऐसी संवैधानिक शक्तियां हैं कि वह संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर सकती है। दलित और आदिवासी संगठनों को क्या आशंका थी कि उन्होंने 'भारत बंद' का आह्वान किया और देश के कुछ हिस्सों में अराजकता फैलाई। उनका आरक्षण सुनिश्चित है।

एमडी एवं एमएस छात्रों के मामलों में यह संख्या 31 प्रतिशत दर्ज की गई

मेडिकल छात्रों में बढ़ रही है मानसिक दुर्बलता

प्रमोद भार्गव

यह कितनी विडंबनापूर्ण बात है कि जो विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा हासिल कर रहे हैं, वही तनावग्रस्त होकर मानसिक दुर्बलता के शिकार हो रहे हैं। जबकि चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व होना चाहिए? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के एक कार्यबल ने ऑनलाइन सर्वेक्षण करके बताया है कि मेडिकल के लगभग 28 प्रतिषत स्नातक और 15.3 प्रतिशत स्नातकोत्तर छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझने की बात स्वीकारी है। सर्वेक्षण में 25,590 स्नातक छात्र, 5,337 स्नातकोत्तर छात्र और 7,035 संकाय सदस्यों ने भागीदारी की। इस परिणाम के बाद सलाह दी गई है कि रेजिडेंट डॉक्टर प्रति सप्ताह 74 घंटे से अधिक काम न करें। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी लें और प्रतिदिन सात से आठ घंटे नींद लें। मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर आई राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 महीनों में 16.2 फीसदी एमबीबीएस छात्रों ने मन में स्वयं को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने के विचार आने की बात मानी है। जबकि एमडी एवं एमएस छात्रों के मामलों में यह संख्या 31 प्रतिशत दर्ज की गई है। रपट के मुताबिक छात्रों में अकेलेपन या सामाजिक अलगाव की भावना तेजी से पनप रही है। 35 फीसदी छात्र इसका अकसर अनुभव करते है और 39.1 फीसदी छात्रों ने कभी-कभी इस विकृत भावना का अनुभव किया है। साफ है, सर्वे का यह पहलू चिंताजनक है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। चिकित्सक और चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले छात्रों में जानलेवा तनाव का उभरना वाकई चिंता का विशय है। चिकित्सा षिक्षा एक तो लंबे समय तक चलने वाली सबसे कठिन और उबाऊ पढ़ाई है, दूसरे पेषे में आने के बाद सबसे ज्यादा गंभीर दायित्व का निर्वहन करना भी है। ऐसे में कोलकाता की प्रषिक्षु महिला चिकित्सक के साथ घटित दुश्कर्म एवं हत्या के मामले छात्रों में अतिरिक्त भय और तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। चिकित्सकों के साथ मरीजों और उनके परिजनों द्वारा दुव्र्यवहार

और मारपीट सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी चिकित्सालयों तक आम बात हो गई है। कई मामलों में उपचार के दौरान रोगी की मौत को परिजन चिकित्सक की लापरवाही ठहराने लगे हैं। ऐसे मामलों में अस्पतालों में मारपीट और तोड़फोड़ के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, जातिगत और संप्रदाय विषेश के लोग अस्पताल में समूह की ताकत दिखाकर पुलिस और प्रषासन को पंगु बना देने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे मामलों में निर्दोश चिकित्सक के विरुद्ध दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। राजनीति भी अकसर जाति और संप्रदाय के समूह के साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में कानून की संहिताएं बोनी दिखाई देती हैं। जब दबाव में ही काम करना है तो कठोर कानून का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 18.2 प्रतिशत चिकित्सा छात्रों को शंकाएं और परामर्श दाताओं से भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। क्योंकि वे खुद डर की दहशत में आ चुके होते हैं। ऐसे माहौल में तनाव से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल की कमी की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण मात्र झुनझुना है। सर्वेक्षण में 56.6 प्रतिशत छात्रों ने अपने शैक्षणिक भार को संभालने योग्य परंतु अत्याधिक बताया। 20.7 फीसदी छात्रों ने शैक्षणिक भार बहुत ज्यादा बताया। केवल 1.5 फीसदी छात्रों ने इसे हल्का बताया। सर्वेक्षण में पाया गया कि 'असफलता का डर' स्नातकोत्तर छात्रों में एक अहम्मुद्दा है। जिसमें 51.6 फीसदी सहमत हैं, कि यह उनके प्रदर्शन पर नकारात्मक असर डालता है। असफलता का यह डर देष के कोचिंग संस्थानों में एमबीबीएस में प्रवेष लेने की प्रतिस्पर्धा में लगे छात्रों को सता रहा है। इसलिए लगातार देखने में आ रहा है कि कोचिंग संस्थाओं के बड़े केंद्र कोटा में छात्र निरंतर आत्महत्या कर रहे हैं। देष के 322 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से प्रत्येक वर्श 48,012 छात्रों को नीट के माध्यम से प्रवेष दिया जाता है। इसके अलावा इन्हीं कॉलेजों से 27,868 दंत चिकित्सक, 52,720 आयुश और 603 पषु चिकित्सक छात्रों को प्रवेष की सुविधा मिलती है। यदि निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने वाले छात्रों को भी जोड़ लिया जाए तो देष के करीब 707 मेडिकल कॉलेजों में 1,09048 छात्र प्रवेष लेते हैं। इनके अलावा दूसरे देषों से भी छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करके भारत में आकर चिकित्सा का पेषा अपना लेते हैं। वैष्विक स्तर पर भारतीय चिकित्सकों की उम्दा साख है। दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा षिक्षा प्रणाली भी भारत में है। इसलिए अब उम्मीद की जा सकती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर की मौजदूगी अनिवार्य है, वह लक्ष्य आने वाले कुछ समय में पूरा हो जाएगा। फिलहाल हमारे यहां यह अनुपात 0.62.1000 है। अब तक सरकारी चिकित्सा संस्थानों की षैक्षिक गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लगभग 60 प्रतिषत मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं। ये संस्थान छात्रों से भारी-भरकम षुल्क तो वसूलते ही हैं, कैपीटेषन फीस लेकर प्रबंधन के कोटे में छात्रों की सीधी भर्ती भी करते हैं। यह दर 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक बताई जाती है। इस सुविधा में आरक्षण और योग्यता के दावे ढकोसला हैं। विष्वबैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 प्रतिषत भारतीय चिकित्सक डिग्री हासिल करने के बाद विदेष चले जाते हैं। इनमें से डेढ़ हजार डॉक्टर अमेरिका का रुख करते हैं। एलोपैथी चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि आज के विद्यार्थी उन पाठ्यक्रमों में अध्ययन करना नहीं चाहते, जिसमें विशेषज्ञता प्राप्त करने में लंबा समय लगता है।

सर्वेक्षण में 25,590 स्नातक छात्र, 5,337 स्नातकोत्तर छात्र और 7,035 संकाय सदस्यों ने भागीदारी की। इस परिणाम के बाद सलाह दी गई है कि रेजिडेंट डॉक्टर प्रति सप्ताह 74 घंटे से अधिक काम न करें। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी लें और प्रतिदिन सात से आठ घंटे नींद लें। मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर आई राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 महीनों में 16 .2 फीसदी एमबीबीएस छात्रों ने मन में स्वयं को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने के विचार आने की बात मानी है।

दृष्टि कोण

भारतीय समाज की पहचान का प्रश्न

हिंदू की पहचान को लेकर बहस कभी बंद नहीं होती। इस बहस की शुरुआत भारत में अरबों, तुर्कों, मुगलों, पुर्तगालियों व अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुई। उससे पहले इस प्रश्न पर बहस नहीं होती थी। ये सभी विदेशी हमलावर या तो इस्लाम पंथ को मानने वाले थे या फिर ईसाई मत को मानने वाले थे। इन लोगों का सामाजिक-सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन इन दोनों में से किसी एक रिलीजन से समग्र रूप में संचालित होता था। उनकी पहचान के आधार भी निश्चित थे/हैं। जो व्यक्ति न्यू टैस्टामैंट में विश्वास करता है, ईसा मसीह को परमात्मा का पुत्र मानता है और चर्च में जाकर पूजा करता है, वह ईसाई है। इसी प्रकार इस्लाम पंथ को मानने वालों की पहचान भी निश्चित थी। जो व्यक्ति हजरत मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है, कुरान शरीफ को स्वीकारता है, मस्जिद में जाकर ईश्वर की इबादत करता है, वह इस्लाम पंथ को मानने वाला यानी मुसलमान है। जाहिर है जब एक निश्चित स्थान पर जाकर पूजा करता है तो वहां पूजा का कर्मकांड करवाने वाला भी चाहिए। इस्लाम पंथ में यह पूजा पाठ करवाने वाला मुल्ला मौलवी था। हर मस्जिद का एक मौलवी निश्चित था। उसे वायज, मीरवायज या इमाम कहा जाता था। इसी प्रकार ईसाई पंथ में पूजा का स्थान चर्च कहलाने लगा और वहां पूजा पाठ करवाने वाला व्यक्ति पादरी कहलाने लगा। लेकिन धीरे ईसाई पंथ में पूजा करवाने वाले लोगों की एक पूरी संगठित जमात खड़ी हो गई जिसका मुखिया पोप कहलाता है। जब ये हमलावर हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले तो इन्होंने ईसाई पंथ व इस्लाम पंथ की तर्ज पर हिंदू को भी एक पंथ या रिलीजन ही मान लिया। उसके बाद ये लोग इस रिलीजन की पहचान करने का प्रयास करने लगे। हिंदू, जिसे इन्होंने रिलीजन समझ लिया था, उसकी पहचान समझने के लिए इन्होंने अपने अपने रिलीजन के पैमाने ही प्रयोग करने शुरू किए। लेकिन मामला पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि भारतीय/हिदू समाज को समझने के लिए जिन कारकों का प्रयोग किया जा रहा था, वे कारक ही गलत थे। यह संकट प्रत्यक्ष रूप में 1881 में सामने आया जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कुल जनसंख्या की गणना करने के लिए एक नया विभाग स्थापित किया। जनगणना करवाना तो आसान काम ही था। लेकिन सरकार ने लगे हाथ मजहब/रिलीजन के आधार पर भी संख्या जान लेना जरूरी समझा। इसलिए जनगणना फार्म में रिलीजन को लेकर तीन कॉलम बनाए गए। हिंदू/मुसलमान/ईसाई। जाहिर है इससे स्पष्ट पता चल गया कि हिंदुस्तान में 712 के बाद से देश में कितने लोग मुसलमान या ईसाई बन गए हैं। एटीएम (अरब-तुर्क-मुगल) मूल के मुसलमानों के सात-आठ सौ साल के शासन के दौरान कुछ करोड़ भारतीय/हिंदू भी मतांतरित हो गए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ भारतीय ईसाई भी हो रहे थे। जाहिर है उनकी संख्या भारतीयों/हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम ही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना और 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेज शासकों ने मजहब के आधार पर कुछ सीमित संख्या में भारतीयों को भी स्थानीय प्रशासन में हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया था। तब एटीएम मूल के मुसलमानों को जिनका शासन समाप्त हो चुका था, इस बात की चिंता हुई कि संख्या के कारण अब उनको सत्ता मिलने की संभावना कम हो गई थी। इसलिए सबसे पहला काम तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को भी अपने खेमे में जोडऩे या हांकने के प्रयास शुरू किए। लेकिन इसके बावजूद उनकी संख्या भला कितनी हो सकती थी? इसलिए दूसरा प्रयास किसी तरह से हिंदुओं की संख्या कम करने के प्रयास किए। लेकिन यह काम अंग्रेज शासकों की मदद के बिना नहीं हो सकता था क्योंकि अब सत्ता तुर्कों-मुगलों के हाथ में नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड के गोरों के हाथ में थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बकौल बाबा साहिब अंबेडकर, एटीएम मूल के आगा खान ने 1910 की जनगणना से पहले वायसराय को एक ज्ञापन दिया। उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने जनगणना के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो पैमाने निर्धारित किए। परोक्ष पैमाना तो यह था कि ब्रिटिश सरकार ने हिदू समाज को सीमित करते हुए हिंदू केवल उसी को माना जो 'जाति व्यवस्था' से संचालित था, जबकि वस्तुस्थिति यह थी/है कि हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जाति व्यवस्था से बाहर है। एक नई अवधारणा स्थापित करने का प्रयास पहली बार हुआ कि सभी भारतीय/हिंदू जाति व्यवस्था से संचालित हैं। मूल रूप से यह अवधारणा ही गलत है। सभी भारतीय/हिंदू जाति व्यवस्था से संचालित नहीं हैं। हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जाति व्यवस्था से संचालित नहीं है। मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश समुदाय मसलन मिजो, कुकी, खासी, गारो, निशी, शेरदुखपेन, संथाल, गोंड, पश्चिमोत्तर भारत में भोट, बलती जाति व्यवस्था से संचालित नहीं हैं। इस निराधार अवधारणा को आधार बना कर जनगणना अधिकारियों ने हिंदू को पहचानने के लिए नई कसौटियां बनाईं। जो उन कसौटियों पर पूरा नहीं उतरता था उसे हिंदू की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इनमें से एक कसौटी ब्राह्मण को लेकर थी।

कुछ अलग

आजाद तोते की राम कहानी

मैंने ही क्या, उस तोते को मेरे पिताजी ने ही पाल रखा था। मेरे घर के पिंजरे में तोता चने की दाल चुगता और पानी पीकर वर्षों से मेरा प्रिय तोता हो गया था। तोता पालने का मुझे शौक भी था और उससे मिलने वाली सूचनाओं से मैं चौकस भी रहता था। तोता भी खुश था, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। एक दिन कुछ पर्यावरण प्रेमी मेरे घर के बाहर आए और नारेबाजी करने लगे। मैं और मेरी पत्नी घबराए से बाहर आए। देखा तो पंद्रह-बीस लोग हाथों में तख्ती थामे तोते की आजादी के लिए मुझसे मांग कर रहे थे। मैंने छद्म पर्यावरण प्रेमियों से कहा भी कि तोता मेरे पुरखों ने पाला है और वह मेरे यहां आराम में है। लेकिन उन्होंने तोते को नहीं छोडऩे पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। पत्नी और मैं दोनों भौंचक्के रह गए। मैंने पत्नी से पूछा - 'बोलो, क्या करें?' पत्नी ने मुझे आंख मारकर कहा -'जनमत का सम्मान करते हुए हम तोते को छोड़ देते हैं।' पर्यावरण प्रेमी खुश हो गए और बोले, 'हमारे सामने ही पिंजरे को खोलो और तोते को आजाद करो।' मैं पिंजरा बाहर ले आया और उसका दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद भी तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकला और पिंजरे में ही शोर मचाने लगा। मैंने पर्यावरण प्रेमियों को विवशता से देखा तो उनमें से एक बोला -'हम आजाद करते हैं इसे।' उसने आगे बढक़र तोता हाथ में पकड़ा और हवा में उछाल दिया। वर्षों से पिंजरे में रहने के कारण तोता भली प्रकार से उड़ नहीं पा रहा था और वह पास के ही एक मकान की छत पर हांफ कर बैठ गया। हम और पर्यावरण प्रेमी उसकी अगली उड़ान की प्रतीक्षा करने लगे। दस-पंद्रह मिनट बाद में तोते ने पंख फैलाए और आसमान में गायब हो गया। पर्यावरण प्रेमी खुश होकर चले गए। लेकिन हमारा मन अवसाद से भर गया। रह-रह कर तोते की याद सता रही थी। उसकी उपयोगिता पर हम इतने निर्भर हो गए थे कि हमें लगा कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। आखिर में पत्नी ने कहा -'चलो देखते हैं, आगे का जीवन कैसे चलता है। चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा।' इसी भावना से हम अपना रहा-सहा समय निकालने लगे। सौभाग्य से मैंने वह पिंजरा फेंका नहीं था और उसका दरवाजा खोल रखा था। अचानक एक दिन तोता उड़ता-उड़ता आया और पुनः पिंजरे में आ बैठा। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हुए कि हमारा तोता हमारे पास वापस लौट आया है। मैंने भरे मन से तोते से कहा -'यार मिट्ठू तुम आ तो गए, लेकिन वे लोग फिर आ जाएंगे और मुझे व्यर्थ में बदनाम करेंगे।' तोता परेशान सा बोला -'नही, मैं नहीं जाऊंगा। वे लोग मुझे आजाद करने के बहाने अब अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। वे मेरे पीछे पिंजरा लेकर भागे फिर रहे हैं।' तोते की बात सुनकर हम घबरा गए। मैंने कहा -'भाई तुम आकाश में ऊंची उड़ान भरो और गायब हो जाओ। वरना वे लोग इधर आने वाले होंगे।' तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकला तो मैंने उसे जीवन सूत्र दिया और कहा -'ऐसा करो मेरे प्यारे मिट्ठू, तुम कभी हमारे पिंजरे में तो कभी उनके पिंजरे में रह लो। इससे तुम्हारा जीवन आराम से निकलता रहेगा। वरना वे लोग मुझे और तुम्हें बदनाम कर देंगे।' तोते को मेरी बात समझ में आ गई और बोला -'यह ठीक है, पिंजरे का दरवाजा खुला रखो, उनका शोर सुनकर मैं उनके पिंजरे में जा बैठूंगा।' मुझे भी बात जंच गई कि तोते को आजादी देने का यह सूत्र सबसे सफल है। अभी तोता मेरे यहां ही है।

देश दुनीया से

शिक्षा विभाग राज्य में खेलों को बढ़ावा देगा?

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने तीन वर्ष पहले अपने पूर्व में रहे खिलाड़ी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के लिए एक पत्र निकाला था। इस पत्र में शिक्षा निदेशालय ने शौकिया प्रशिक्षण करवाने वाले इच्छुक शिक्षकों व कर्मचारियों के नाम मांगे थे ताकि उन्हें प्रशिक्षण सुविधाओं वाली जगहों पर नियुक्त किया जा सके। मगर आज तक भेजे गए उन नामों का कुछ पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। अब शिक्षा निदेशालय एक बार फिर अपने पूर्व में रहे खिलाड़ी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों से स्कूल के बाद खेल प्रशिक्षण दिलाने के बारे में सोच रहा है। देखते हैं कब तक इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों खिलाड़ी खेल आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। दर्जन भर खिलाडियों को छोड़ कर न तो कोई खेल कर रहा है और न ही प्रशिक्षण व अन्य खेल प्रबंधन से जुड़ा है। खेलों से नियमित रोजी-रोटी मिलने वालों को चाहिए कि वे नमक का कुछ तो हक अदा करें। अगर खिलाड़ी के रूप में नहीं हो सकता है तो प्रशिक्षण व प्रबंधन तो आसानी से हो ही सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में खेल आरक्षण के अंतर्गत तीन प्रतिशत पदों पर भर्ती करती है। शिक्षा विभाग में अब तक सैंकड़ों प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक व अन्य पदों पर खेल आरक्षण से शिक्षक नियुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश का हर बच्चा विद्यालय जा रहा है। वैसे तो विद्यालय में विद्यार्थियों की फिटनेस व खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा का शिक्षक नियुक्त होता है, मगर वह हर खेल के लिए प्रशिक्षण नहीं दे सकता है। भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए किशोरावस्था से ही सही तकनीक के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। अरबों की आबादी में किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का प्रारंभिक स्तर से होना बेहद अनिवार्य हो जाता है, जो सही उम्र में सही तकनीक सिखा कर भविष्य में खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। हिमाचल प्रदेश में खेल प्रशिक्षण के लिए शुरू से वह वातावरण ही नहीं बन पा रहा है, जिससे बाद में प्रशिक्षक खिलाड़ी से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठतम परिणाम दिला सके। खेल प्रशिक्षण दस साल से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतने लंबे खेल प्रशिक्षण को प्राप्त कर कुछ एक खिलाड़ी ही अपने प्रदेश व देश को गौरव दिला पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षकों की कमी सबके सामने है। विद्यालय जीवन ही वह समय है जब खिलाड़ी तकनीक को सीख रहा होता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलने से पहले व बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों को छोड़ कर अन्य विषयों के शिक्षक जो पूर्व में अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अपने पढ़ाई के कार्य के साथ-साथ विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम पूर्व में रोशन करते रहे हैं और वर्तमान में कर भी रहे हैं। हमीरपुर शहर के वरिष्ठ माध्यमिक कन्या राजकीय विद्यालय में चार दशक पूर्व नियुक्त प्रयोगशाला सहायक अमरनाथ शर्मा ने हमीरपुर से महिला हाकी के लिए निचले स्तर पर बहुत अच्छा काम किया था। इस तरह और कई नाम हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ खेल प्रशिक्षण में भी सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान में बिलासपुर जिले के दूरदराज मोरसिंघी गांव के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता व पूर्व अंतरराष्ट्रीय हैंडबाल खिलाड़ी स्नेहलता के प्रशिक्षण कार्यक्रम से राष्ट्रीय स्तर पर हर आयु वर्ग की महिला प्रतियोगिताओं में हिमाचल विजेता है। पिछले एशियाड में भारतीय महिला हैंडबाल टीम में चार खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से थी। इस साल की राष्ट्रीय महिला हैंडबाल प्रतियोगिता की विजेता हिमाचल प्रदेश की टीम में अधिकांश खिलाड़ी मोरसिंघी नर्सरी से हैं। स्नेहलता की पहली नियुक्ति शिक्षा विभाग में सोलन जिले के नवगांव वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। उसी समय से स्नेह लता ने हैंडबाल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक दशक पूर्व हमीरपुर जिले के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्डयार में नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था। उसके अच्छे परिणाम रहे थे। मगर बाद में ऐसी जगह ट्रांसफर हो गई जहां प्ले फील्ड व समय की दिक्कत के कारण उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद हो गया। हमीरपुर में आज अपने समय के स्टार धावक अनिल शर्मा व रजनीश शर्मा जो दोनों ही प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के बाद शाम के समय अणु सिंथेटिक ट्रैक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हुए हैं।

तीन वर्ष पहले अपने पूर्व में रहे खिलाड़ी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के लिए एक पत्र निकाला था। इस पत्र में शिक्षा निदेशालय ने शौकिया प्रशिक्षण करवाने वाले इच्छुक शिक्षकों व कर्मचारियों के नाम मांगे थे ताकि उन्हें प्रशिक्षण सुविधाओं वाली जगहों पर नियुक्त किया जा सके। मगर आज तक भेजे गए उन नामों का कुछ पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। अब शिक्षा निदेशालय एक बार फिर अपने पूर्व में रहे खिलाड़ी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों से स्कूल के बाद खेल प्रशिक्षण दिलाने के बारे में सोच रहा है। देखते हैं कब तक इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों खिलाड़ी खेल आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। दर्जन भर खिलाडिय़ों को छोड़ कर न तो कोई खेल कर रहा है और न ही प्रशिक्षण व अन्य खेल प्रबंधन से जुड़ा है।

आप का नजरीया

महिला सुरक्षा का प्रश्न

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक की यौन हिंसा के बाद हुई हत्या ने एक बार फिर साबित किया है कि देश में कामकाजी महिलाओं के लिये कार्यस्थल पर परिस्थितियां कितनी असुरक्षित हैं। वह भी इतनी भयावह कि कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ यह सब वीभत्स घट जाता है। निश्चित रूप से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन ही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये सुरक्षा अनुकूल वातावरण बनाने के मद्देनजर विशाखा दिशा-निर्देश जारी करने के सत्ताईस साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को डॉक्टरों की सुरक्षा को संस्थागत बनाने के लिये तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुपालन हेतु गठित एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स को चिकित्सा पेशवरों की सुरक्षा, महिला चिकित्सकों के लिये अनुकूल कामकाजी परिस्थितियां बनाने तथा उनके हितों की रक्षा के लिये प्रभावी सिफारिशें तैयार करने का काम सौंपा गया है। विश्वास किया जाना चाहिए कि ये सिफारिशें यदि जमीनी स्तर पर भी प्रभावी साबित हुईं तो किसी भी पेशे में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिये असरकारी साबित होंगी। लेकिन यह तभी संभव है जब सभी हितधारक एक स्तर पर एकजुट होकर इस दिशा में काम करेंगे। निस्संदेह, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने के वक्त तमाम तरह के उपक्रम होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही वजह है कि नई कार्ययोजना बनाते समय इस बात का आकलन करने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है कि महिला सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानून और दिशा-निर्देश जमीनी स्तर पर बदलाव लाने में कितने सफल रहे हैं। सही मायनों में कानून बनाने और दिशा-निर्देश जारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अनुपालन कितने पारदर्शी व संवेदनशील दृष्टि से किया जाता है। साथ ही विगत के अनुभवों से भी सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद देश में कोलकाता कांड में भी उसी तरह की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है। जिसके बाद आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे क्रूर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने वाले कानून लाये जाएं। कालांतर देश में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम अस्तित्व में आया। दरअसल, महिलाओं के लिये सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ही विशाखा दिशा-निर्देशों के विस्तार के रूप में इसे अधिनियमित किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि पिछले साल, देश की शीर्ष अदालत ने इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था। साथ ही इससे जुड़ी अनिश्चितताओं की ओर भी संकेत दिया था। इसके उदाहरण के रूप में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निर्भया फंड अक्सर नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहा है।

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक किसी कीमत पर संसद से पारित नहीं होने देंगे : तेजस्वी यादव

पटना (हिंस)। बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को मुक्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदार से मुलाकात की। साथ ही उनसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बातचीत की। तेजस्वी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वे इस विधेयक को किसी भी कीमत पर संसद से पारित नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्विट कर कहा कि मुक्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के ओहदेदार *वक्फ बोर्ड संशोधन बिल* के सिलसिले में मिले और वाजेह और तफ्सील-वार गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद शुरू से ही अकलियत के हरेक मुद्दे पर संवेदनशील रहे हैं और किसी भी धार्मिक मामलों में सरकार के दखल-अंदाजी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से ना सिर्फ मुस्लिम, बल्कि दीगर मजहबों के

मजहबी, सकाफती और जायदाद के हुकूक पर असर पड़ेगा और एक गलत नजीर कायम होगी। हमारी पार्टी मोदी-नीतीश एनडीए की इस गैर संवैधानिक, गैर जरूरी प्रस्तावित संशोधन बिल, जो कि मुल्क के सेक्युलर ताने-बाने को तोड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने के मकसद से लाया गया है उसका पुरजोर विरोध करती है। तेजस्वी ने डेलीगेशन को तसल्ली दिलाया कि हम उनके साथ हैं और किसी कीमत पर इसको संसद से पारित नहीं होने देंगे और इस लड़ाई को सभी फोरम पर लड़ेंगे। अफसोस है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बिल के समर्थन में हैं। तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश को कई मामलों को लेकर घेर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने सीएम के समर्थन को लेकर अफसोस जाहिर किया है। उल्लेखनीय है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) की बीते दिन गुरुवार यानी 22 अगस्त को दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में बैठक हुई। लगभग छह घंटे तक चली जेपीसी की मीटिंग में अधिकतर सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट नजर आए। बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों ने कई मुद्दों पर नाराजगी जताई। विपक्षी सांसद बोले, *यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई अन्य कानूनों का पूर्ण उल्लंघन है।*

अधिकारी करदाता के प्रति सकारात्मक रहें : केंद्रीय वित्त मंत्री

उदयपुर (हिंस)। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को उदयपुर में हिरणमगरी सेक्टर-14 में नवनिर्मित जीएसटी भवन का दीप प्रज्ज्वलित कर तथा फीता काटकर लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि करदाताओं की सहूलियत के लिए 2019 से ही जीएसटी के कार्यालयों को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। इससे करदाताओं के मन में कोई सवाल हो या कोई समस्या हो तो आसानी से जा कर उनका समाधान करा सके। उन्होंने कहा कि अधिकारी और करदाताओं के बीच माहौल सकारात्मक होने से समस्या के समाधान करने में दिक्कत नहीं आएगी। जीएसटी कौंसिल में भी अधिकारी और मंत्री समस्याओं का तत्काल समाधान कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यहां के सीमेंट, टायर, फर्टिलाइजर्स, उद्योग एवं खनिज क्षेत्र का जीएसटी में बड़ा योगदान है, लेकिन अब छोटे उद्योग भी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मोबाइल एप के आने से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में मदद मिली है। उदयपुर में सबसे ज्यादा जीएसटी रेवेन्यू जिंक से आता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक और पान मसाला से भी काफी जीएसटी आता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए और अधिकारी करदाता के प्रति सकारात्मक रहें, जिससे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता ही न पड़े। उन्होंने कहा कि आज जो आइस टैब एप लॉन्च किया है इससे आयातक निर्यातकों को माल तत्काल भेजने में सहायता

मिलेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि उदयपुर में जो ये भवन बना है उसके लिए हमने 42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, लेकिन यह लगभग 32 करोड़ रुपए में ही बन गया। उन्होंने कहा कि करदाताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान होना चाहिए, इससे शंका समस्या में नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी अधिकारियों को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि वो करदाताओं की मदद के लिए तत्पर रहें जिससे व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। प्रारंभ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि इस भवन में हमने करदाताओं की सुविधा के लिए प्रावधान किए हैं एवं पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। उन्होंने जीएसटी संग्रहण के बारे में अवगत करवाया।

सड़क हादसे में तीन जनों की मौत

बीकानेर (हिंस)। जिले के नोखा थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में तीन जनों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। जानकारी मिली है कि रासीसर में भारत माला रोड पर दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायल को राहगीरों की मदद से पीबीएम अस्पताल लाया गया। जहां घायल का इलाज जारी है। मृतकों की पहचान रासीसर निवासी ओमप्रकाश, सुरेश व जगदीश के रूप में हुई है। जबकि घायल सोहनलाल का इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद हाइवे पर जाम लग गया था। बीकानेर पुलिस ने दोनों गाड़ियों को मौके से हटाकर जाम खुलवाया। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ को भी रास्ता खोलने के लिए कहा। घटना के बाद कई लोग इसका वीडियो बनाते हुए भी दिखे। वहीं अभी तक हादसे का कारण नहीं पता चल पाया है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। मृतकों के शवों को स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दरअसल बारिश होने के चलते सड़क भीगी हुई थी। ऐसे में शुरुआती अंदेशा लगाया जा रहा है कि फिसलन के चलते चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया होगा।

पंजाब के राज्यपाल की तबीयत में सुधार, अस्पताल से मिली छुट्टी

उदयपुर (हिंस)। अपने घर उदयपुर आए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया की गुरुवार देररात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तत्काल उदयपुर के राजकीय एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। रात भर भर्ती रखने के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर शुक्रवार सुबह उन्हें छुट्टी दे गई। बताया गया है कि गुरुवार रात को माछला मगरा स्थित निवास पर कटारिया को सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद तत्काल पास के ही डॉक्टर को बुलाया गया और ब्लड प्रेशर की जांच की गई। बीपी बड़ा हुआ होने से डॉक्टर के अस्पताल जाने की सलाह पर कटारिया का स्टाफ उनको सीधे अस्पताल लेकर रवाना हुआ। उन्हें रात करीब 11:15 बजे एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उन्हें कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू में रखा गया। कटारिया के घर से रवाना होने से पहले अस्पताल को सूचना कर दी गई, जिससे वहां डॉक्टर्स की टीम भी अलर्ट हो गई। अस्पताल में कटारिया का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उनकी जांचें कराई गई।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस

नारनौल (हिंस)। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि) महेंद्रगढ़ में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग के नक्षत्र क्लब द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया गया। आयोजन में जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान पीठ के प्रो. पवन कुमार जोशी विशेषज्ञ वक्ता के रूप में मौजूद रहे। विशेषज्ञ वक्ता प्रो. पवन कुमार जोशी ने अपने संबोधन में उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। प्रो. जोशी ने भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत और इसकी चुनौतियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया। उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुदूर संवेदन तकनीक, वन और जैव विविधता मानचित्रण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए अनुप्रयोगों पर भी चर्चा की। उन्होंने उभरती हुई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिवर्ष इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने, अंतरिक्ष

अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने और भविष्य में अधिक शिक्षण संस्थानों को इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल करने की सिफारिश की। आयोजन में खगोल विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा निर्देशित, आकाशीय पिंडों के अवलोकन के लिए स्थापित दूरबीनों पर केंद्रित इंटरैक्टिव का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंगोली, पेंटिंग, अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इनमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 60 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतिभागिता की। कार्यक्रम में डॉ. अंकुश विज, डॉ. मीनू ठाकुर, डॉ. राकेश, डॉ. रामोवतार, डॉ. जसवंत, डॉ. मोना, डॉ.स्वाति, डॉ. मीनू ठाकुर, डॉ. संगीता, डॉ. प्रदीप सहित नक्षत्र क्लब के स्वयंसेवक आदि मौजूद रहे।

चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय के पीएमओ को किया एपीओ

चित्तौड़गढ़ (हिंस)। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े चिकित्सालय श्री सांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के लंबे समय से प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ) के पद पर आसीन डॉ. दिनेश वैष्णव को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आदेश देकर पदस्थापन की प्रतिक्षा में (एपीओ) कर दिया है। इनके स्थान पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जयसिंह मीणा को जिला चिकित्सालय का चार्ज सौंपा है। पीएमओ वैष्णव के खिलाफ एक महिला चिकित्सक को गत वर्ष डबल भुगतान की शिकायत थी, जिसमें दोषी माना। एपीओ आदेश में भी सीसीए नियम-16 के तहत कार्रवाई विचाराधीन होने का हवाला दिया है। लेकिन चर्चा यह भी है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएमओ ने ध्वजारोहण के बाद राजनीतिक भाषण दिया था, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। इसके चलते पीएमओ पर गाज गिरी हो। जानकारी के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीना ने गुरुवार देर रात को आदेश जारी किया। इसमें बताया कि जिला चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के पीएमओ डॉ. दिनेश वैष्णव के खिलाफ सीसीए नियम-16 के अंतर्गत कार्रवाई विचाराधीन है। इसलिए, प्रशासनिक कारण और लोक हित को देखते हुए वैष्णव को एपीओ किया गया। एपीओ के कार्यकाल में उन्हें मुख्यालय निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के कार्यालय में अपनी सेवाएं देनी होगी। वहीं, दूसरे आदेश में संयुक्त शासन सचिव ने महिला एवं बाल चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ में तैनात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. जयसिंह मीणा को जिला चिकित्सालय के पीएमओ नियुक्त किया। साथ ही, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तीन के अंतर्गत कार्यालय अध्यक्ष भी घोषित किया। जानकारी में सामने आया कि डॉ. दिनेश वैष्णव के खिलाफ पिछले साल चार्जशीट पेश की गई थी। डॉ. वैष्णव पर जिला चिकित्सालय में ही महिला चिकित्सक को चिकित्सालय के दो विभाग का कार्यभार दिया गया था। डॉ. वैष्णव लगातार महिला चिकित्सक को दोनों विभाग एचआईवी और डायलासिस में काम करने के कारण डबल भुगतान कर रहे थे। ज्वाइंट डायरेक्टर तक इस बात की जानकारी पहुंची तो जांच कमेटी गठित की थी। जांच के बाद डॉक्टर वैष्णव पर दोष सिद्ध भी हो गया था। इस स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद दिया पीएमओ वैष्णव का भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। वैष्णव ने कहा कि बहुत लोग साफा पहनने और झंडारोहण की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। यहां मैं यही रहूंगा और अगले 365 दिनों तक रहूंगा। जब समय आएगा तो उससे पहले ही मैं इस चीज से निपटान करूंगा। अभी डबल इंजन की सरकार है और तीसरा इंजन भी आ गया है, जो इस चिकित्सालय में काम कर रहा है। यह सांवलियाजी हॉस्पिटल है, यहां पर सिर्फ सांवरा सेठ की ही चलेगी। चाहे कितने भी इंजन आ जाए मैं यही इसी पद पर रहूंगा। सूत्रों की मानें तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में डॉ. दिनेश वैष्णव कांग्रेस नेताओं के खास माने जाते रहे हैं। इस दौरान भाजपा नेताओं से खींचतान भी हुई थी। यही कारण है कि अनियमितता की शिकायत होने के बावजूद भी पद पर बनाए रखा था। वहीं प्रदेश में भाजपा राज आने के बाद वैष्णव नेताओं के यहां भी देखे गए थे।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई : पंकज अग्रवाल

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आमचुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की पालना सख्ती से करें। कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकता है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रचार करने के लिए होर्डिंग व बैनर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से निर्धारित किए गए स्थानों पर ही लगाने होंगे, जिनकी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान वितरित किए जाने वाले सभी पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व नंबर अंकित होना सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन निर्देशों का पालन न करने पर प्रिंटिंग प्रेस व सामग्री वितरित करने वाले दल या उम्मीदवार के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोलकाता की घटना से आहत निजी स्कूली छात्राओं ने सड़क पर निकल किया प्रदर्शन, वी फॉर जस्टिस के लगाए नारे

गोपालगंज (हिंस)। कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज में हुई मामले को लेकर शहर में सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्राओं ने शुक्रवार को आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया। सभी छात्राएं अपने अपने हाथों में अलग अलग बैनर पोस्टर इंसाफ की मांग कर रही थी। वही समाज में बढ़ रहे महिला अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। डॉक्टर नंदी प्रेस इंग्लिश स्कूल की छात्र छात्राएं प्रिंसिपल सह डायरेक्टर एलोरा नंदी के नेतृत्व में वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए चल रही थी। इस दौरान सभी छात्राएं सरकार और आम जनता से महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में

सहयोग की भी अपील कर रही थी। स्कूल से प्रदर्शन कारी छात्राएं अपने अपने हाथों में तख्ती लेकर कतारबद्ध होकर नारे लगाते हुए मौनिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, सिनेमा रोड, जंगलिया मोड होते हुए अंबेडकर चौक तक गई। फिर वहां से वापस समाहरणालय के सामने से होते हुए अपने स्कूल पहुंच गई। इस प्रकार प्रदर्शन समाप्त हो गया। प्रदर्शन के दौरान संस्थान के प्रमुख नरेंद्र कुमार पंकज के साथ स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिका मौजूद रही। छोटे छोटे स्कूली बच्चे के आखों में महिला अत्याचार के खिलाफ गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। प्रदर्शन करने के बाद सभी छात्राएं जुलुस की शक्ल में नारे लगाते हुए अपने स्कूल तक गई। प्रदर्शनकारी बच्चे की मुख्य मांग यह थी कि किसी भी रूप में बलात्कारी को बचाने का काम कोई नहीं करें। बल्कि जो भी बलात्कारी है उसे सीधे चौराहे पर फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसे घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सबक मिल सके। कोलकाता घटना नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी घटना हो रही है। ऐसी सभी घटना के खिलाफ यह प्रदर्शन है ताकि महिला के खिलाफ अगर कोई अत्याचार होता है तो हम सब उसकी आवाज बने और इंसाफ की लड़ाई लड़ सके।

बीकानेर में रेजीडेंट डाक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त की

बीकानेर (हिंस)। उच्चतम न्यायालय की अपील के बाद अब रेजीडेंट डाक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। सभी रेजीडेंट काम पर लौट आए हैं। शुक्रवार सुबह से ही अस्पतालों के वार्डों, ओपीडी, ओटी में डाक्टरों ने काम शुरू कर दिया है। एक दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता के बाद आपातकालीन सेवाएं डाक्टरों ने शुरू कर दी थी। आज से पूरी तरह से काम पर आ गए हैं। इस स्थित में अब पीबीएम अस्पताल में पूर्व में जो ऑपरेशन टल गए थे, वो अब होंगे। डाक्टरों की हड़ताल टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी पूरी तरह से उपचार मिलेगा, वहीं सामान्य तौर पर ओपीडी में आने वाले मरीजों को चिकित्सा सेवाएं मिल सकेगी।

पिस्टल सटाकर जमीन लिखाने में अब्बास अंसारी को जमानत मंजूर

प्रयागराज (हिंस)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी के साथ ही दोनों की जमानत अर्जियों पर वकीलों को सुनने के बाद गत एक अगस्त को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। मामले के तथ्यों के अनुसार गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में इन सभी पर ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती जमीन थी। मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों के जरिए 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया और उसकी जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया। साथ ही जमीन न बेचने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद सर्किल रेट के आधार पर 20 लाख का चेक और चार लाख नकद देकर बैनामा करा लिया। इस दौरान अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद फखर के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने पिस्टल लगाकर उसे धमकाया और चेक पर साइन करा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। एफआईआर के मुताबिक वारदात में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी शामिल थी। आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद की पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है। जबकि अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है।

मायावती ने एससी-एसटी आरक्षण को लेकर केंद्र को घेरा, कांग्रेस-सपा की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

लखनऊ (हिंस)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने इसको लेकर कांग्रेस और सपा की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। मायावती ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 01 अगस्त को एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर को लेकर नया नियम लागू किया है। इस निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षाओं के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चिंताजनक है। इसको लेकर 21 अगस्त को भारत बंद किया गया, बावजूद अगर केंद्र सरकार इसमें जरूरी सुधार के लिए गंभीर नहीं तो यह सोचने वाली बात है। पहले कोर्ट में लचर पैरवी और अब उसको लेकर संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाने से यह साबित होता है कि भाजपा का एससी-एसटी आरक्षण को लेकर पुराना रवैया बरकरार है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आईएनडीआईए के घटक दलों की चुप्पी उतनी ही घातक है। इससे यह फिर से साबित हो रहा है कि एससी-एसटी वर्गों के कल्याण के मामले में सपा और कांग्रेस समेत आईएनडीआईए के अन्य घटक दल एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण बलराम मंदिर धूम धाम से करेगा यशोदानंदन का अभिनंदन

जयपुर (हिंस)। 26 अगस्त जन्माष्टमी को श्री कृष्ण बलराम मंदिर में भक्त यशोदानंदन का अभिनंदन जयघोष के साथ करेंगे। छोटी काशी जयपुर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कन्हैया के प्रेम और वात्सल्य से सराबोर हो जाएगी। जगतपुरा के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में जन्माष्टमी की विशेष तैयारियां की जा रही है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार इस बार डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जन्माष्टमी महोत्सव की शुरुआत सुबह मंगला आरती से शुरू हो जाएगी जो रात्रि 12 बजे श्रीकृष्ण के जन्म के साथ होने वाली महाआरती के साथ संपन्न होगी। मंदिर के अध्यक्ष अमितासना दास ने जन्माष्टमी की तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए बताया की मंदिर में यशोदानंदन के अभिनंदन की तैयारियां दो महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। यह पर्व श्री कृष्ण बलराम मंदिर में मनाया जाने वाला वर्ष का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उत्सव है। जन्माष्टमी महोत्सव पर श्रीकृष्ण बलराम रेशमी सुनहरी पोशाक धारण करेंगे।

जिसे मथुरा के कारीगरों ने विशेष तौर पर डेढ़ महीने में तैयार किया है। मंदिर अध्यक्ष ने जन्माष्टमी के महाभिषेक के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया की मध्यरात्री को 12 बजे यशोदानंदन का अभिषेक किया जाएगा। जिसमें पूरे जयपुर से लाखों श्रद्धालु उपस्थित होंगे। महा अभिषेक नारियल पानी, दिव्य जल, जड़ी बूटियां, पंचामृत और पंचगव्यों से होगा। जिसे 108 कलशों से किया जाएगा। दिन भर मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन होगा। जिसमें श्रद्धालु भगवान कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नृत्य करेंगे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया की इस बार जन्माष्टमी पर भक्तों को सिर्फ 20 मिनट में भगवान के दर्शन होंगे। जिसके लिए मंदिर में दर्शन के लिए दो पंक्तियां लगाई जाएंगी। मंदिर में भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्किंग के लिए भी बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में 250 सीसीटीवी कैमरे एवं मेटल डिटेक्टर युक्त द्वार भी लगाए जाएंगे। जिसमें से पूरी तरह सुरक्षा जांच के बाद ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंच सकेंगे। अमितासना दास ने जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में नए जीएसटी भवन का किया उद्घाटन

अधिकारियों से कहा-संदेह को शिकायतों में बदलने से रोकें

नई दिल्ली/उदयपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे करों के संबंध में जनता और व्यापारिक समुदाय द्वारा उठाई गई शंकाओं और चिंताओं का सक्रियता से समाधान करें, इससे पहले कि वे शिकायतों में बदल जाएं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के उदयपुर में नए जीएसटी भवन के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में कर-संबंधी मुद्दों से निपटने में निवारक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारियों को समस्याओं को उस स्तर पर हल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जब वे केवल संदेह के स्तर पर हों, बजाय इसके कि उन्हें पूरी तरह से शिकायतों में तब्दील होने दिया जाए।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय से सरकार के मोरेटोरियम और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की मदद से छोटे उद्योग संकट से बाहर आ सके हैं। आप अब और आगे बढ़ें और जीएसटी को लेकर आपके मन में कोई संकोच रहना नहीं चाहिए। हमारी ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी जीएसटी सेंट्रल जोन और आयुक्तालयों के पास उचित भवन, कार्य स्थल तथा सुविधाएं हों, क्योंकि ये वे स्थान हैं, जहां अधिकारी करदाताओं से बातचीत करते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से करदाता की शंकाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुक्तालयों को सूचना साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इससे शिकायत निवारण में स्वत: कमी आएगी।

उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद मन्ना लाल रावत, सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक फूल सिंह मीना और सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे।

इससे पहले राजस्थान के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के दूसरे दिन उदयपुर पहुंचीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथजी के ग्वाल झांकी के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परंपरा के अनुसार रजाई उपरना ओढ़ा कर उनका स्वागत किया गया।

न्यूज़ ब्रीफ

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से शुक्रवार को मिले-जुले संकेत मिले हैं। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार भी पिछले सत्र के दौरान सपाट स्तर पर कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला कारोबार हो रहा है। मुनाफा वसूली का दबाव बनने की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली होती रही, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांकों में गिरावट आ गई। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.89 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,570.64 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 299.63 अंक यानी 1.67 प्रतिशत टूट कर 17,619.35 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। डाउ जॉन्स फ्यूचर्स फिलहाल 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 40,785.45 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करने के बाद मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एफटीएसई इंडेक्स 0.06 प्रतिशत की तेजी के साथ 8,288 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह डीएएक्स इंडेक्स ने 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,493.39 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। दूसरी ओर, सीएसी इंडेक्स 0.01 प्रतिशत की सांकेतिक गिरावट के साथ 7,524.11 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

जन्माष्टमी से पहले सस्ता हुआ सोना, चांदी में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने के भाव में गिरावट आई है। वहीं चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोने के भाव में तेजी आने के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 73 हजार रुपये के स्तर से नीचे आ कर 72,960 रुपये से लेकर 72,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 67 हजार रुपये के स्तर से लुढ़क कर 66,940 रुपये से लेकर 66,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में शुक्रवार को कोई बदलाव नहीं आने की वजह से दिल्ली सर्राफा बाजार में ये चमकीली धातु भी 86,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना 72,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 66,940 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसी तरह मुंबई में 24 कैरेट सोना 72,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 66,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह चेन्नई में भी 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 72,860 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 66,790 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।

सरकार अगले महीने खुले बाजार में गेहूं बेचना शुरू करेगी

नई दिल्ली। सरकार अगले महीने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के भंडार से थोक खरीदारों को खुले बाजार में गेहूं बेचने पर विचार कर रही है। यह फैसला आगामी त्योहारी सीजन में संभावित मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पिछले साल एफसीआई ने जून में खुले बाजार में बिक्री शुरू की थी और 10 मिलियन टन गेहूं की रिकॉर्ड मात्रा थोक खरीदारों को बेची थी। व्यापारियों का कहना है कि मौजूदा आपूर्ति स्थिति पर्याप्त है लेकिन त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर कीमतों में वृद्धि की संभावना हो सकती है। वर्तमान में एफसीआई के पास 25.89 मिलियन टन गेहूं का भंडार है, जबकि अक्टूबर 1 के लिए बफर स्टॉक 20.52 मिलियन टन है। एक आधिकारिक नोट के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 18.4 मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार गेहूं की कीमतों पर निगरानी रखे हुए है, जो पिछले छह महीनों से स्थिर रही हैं। खुले बाजार में गेहूं की बिक्री उस समय शुरू की जाएगी जब कीमतों में वृद्धि की संभावना होगी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने उठाया बड़ा कदम

अनिल अंबानी को शेयर बाजार से किया पांच साल के लिए बैन, 25 करोड़ जुर्माना लगाया

मुंबई/नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फंड की हेराफेरी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को शेयर बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक एजेंसी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उनके किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

सेबी ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी सहित 24 अन्य संस्थाओं पर पूंजी बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना के साथ किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

बाजार नियामक ने जिन लोगों को प्रतिबंधित किया है वे सभी व्यवसायी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से नहीं जुड़ सकेंगे।

इसके अलावा बाजार नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटीटीज को बैन किया है। इन सभी पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन किया है और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच में पता चला कि आरएचएफएल के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर दिया गया है।

डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 90 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा की अगुवाई वाली एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने एयरलाइन पर ये जुर्माना नॉन क्वालिफाइड क्रू के साथ उड़ान संचालित करने के लिए लगाया है।

विमानन नियामक की ओर से शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एयर इंडिया पर नॉन क्वालिफाइड क्रू के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा डीजीसीए ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक तथा प्रशिक्षण निदेशक पर क्रमश: 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का भी जुर्माना लगाया है।

डीजीसीए ने जारी विज्ञप्ति में एयरलाइन से संबंधित पायलट को आगाह किया है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। दरअसल, एयर इंडिया लिमिटेड ने एक नॉन-ट्रेनर लाइन कैप्टन द्वारा संचालित उड़ान का संचालन किया, जिसे एक नॉन-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ जोड़ा गया था। इसको नियामक ने एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है, जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई, 2024 को एयर इंडिया एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के माध्यम से घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की, जिसमें दस्तावेजों की जांच और शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच शामिल थी। डीजीसीए ने जांच के उपरांत ये कार्रवाई की है।

एसएमई लिस्टिंग को लेकर एनएसई सख्त, नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने अपने एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के नियमों को और कड़ा कर दिया है। नए नियम के मुताबिक अब एसएमई सेगमेंट में उन्हीं कंपनियों को लिस्टिंग की इजाजत दी जाएगी, जिनके पास एप्लीकेशन करने के पहले के तीन वित्त वर्षों में कम से कम दो वित्त वर्ष के दौरान पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी (एफसीएफई) होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये नियम 1 सितंबर से लागू हो जाएगा।

एफसीएफई किसी कंपनी द्वारा उत्पन्न की गई वो नकदी होती है, जो कंपनी के सभी कर्जों और पुनर्निवेश (रिइन्वेस्टमेंट) से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के बाद कंपनी के शेयर धारकों के बीच भुगतान किए जाने के लिए उपलब्ध होता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि एफसीएफई का ये अतिरिक्त क्राइटेरिया 1 सितंबर और उसके बाद दाखिल किए जाने वाले सभी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (डीआरएचपी) यानी आईपीओ लाने के लिए सेबी की अनुमति प्राप्त करने वाले प्रारंभिक दस्तावेजों पर लागू होगा। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो एसएमई प्लेटफॉर्म के तहत ले जाने वाले आईपीओ के सभी आवेदन इस नए नियम के तहत परखे जाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पर आईपीओ लाने के लिए पहले से बनाए गए अन्य नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एनएसई की ओर से जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि यह नया नियम अगले आदेश तक जारी रहेगा। शेयर बाजार के जानकारों का कहना है कि इस बात का अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था कि छोटे और रिटेल इंवेस्टर्स के हितों की सुरक्षा के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह का नया नियम लागू कर सकता है। इसके पहले एनएसई ने कुछ दिन पहले ही एसएमई प्लेटफॉर्म के आईपीओ के लिस्टिंग के दिन प्राइस मूवमेंट पर 90 प्रतिशत की बाध्यकारी सीमा लागू की थी। 4 जुलाई को जारी किए गए एनएसई के सर्कुलर में कहा गया था कि एसएमई प्लेटफॉर्म के आईपीओ के लिए स्पेशल प्री ओपन सेशन के दौरान एक्सचेंज में ओपनिंग प्राइस डिस्कवरी यानी इक्विलीब्रियम प्राइस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एसएमई प्लेटफॉर्म के इनिशियल पब्लिक ऑफर्स (आईपीओ) के लिए इश्यू प्राइस पर 90 प्रतिशत तक की कुल सीमा तय करने का फैसला लिया गया है।

रेपको बैंक ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री को 19.08 करोड़ का लाभांश चेक भेंट किया

नई दिल्ली। रेपको बैंक ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को 19.08 करोड़ रुपये का लाभांश चेक भेंट किया। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी दी।

मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार की 76.32 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी पर 25 प्रतिशत की दर से लाभांश के रूप में 19.08 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया गया। मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को रेपको बैंक के अध्यक्ष ई. संथानम और प्रबंध निदेशक (प्रभारी) ओएम गोकुल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार की 76.32 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी पर 25 प्रतिशत की दर से लाभांश के रूप में 19.08 करोड़ रुपये का चेक गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, गृह मंत्रालय में ओएसडी गोविंद मोहन की उपस्थिति में भेंट किया। उल्लेखनीय है कि रेपको बैंक, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक उद्यम है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिजनेस मिक्स में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में शुक्रवार को बैंक ने 20,000 करोड़ रुपये के बिजनेस मिक्स को पार कर लिया है।

भारत ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नहीं बल्कि चाहता है कि वे निष्पक्ष रहें: गोयल

ऑनलाइन कारोबार करने वालों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर सुनिश्चित करने की जरूरत

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहता है कि वे निष्पक्ष और ईमानदार रहें। गोयल ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

गोयल ने हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनियों की बाजार खराब करने वाली कीमतों के बारे में चिंता जताई और देश में छोटे खुदरा विक्रेताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाओं को सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया और ई-कॉमर्स क्षेत्र के बड़े पैमाने पर वृद्धि के साथ बड़े सामाजिक व्यवधान की चेतावनी दी।

गोयल ने हाल ही में यहां एक कार्यक्रम में कहा कि इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि हम एफडीआई लाना चाहते हैं, हम प्रौद्योगिकी को आमंत्रित करना चाहते हैं, हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और हम ऑनलाइन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। देश हमेशा यही चाहता है कि ग्राहकों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार हो, ईमानदारी बरती जाए, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के प्रति ईमानदारी हो और यह सुनिश्चित हो कि अन्य लोगों को भी ऐसे ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिले। गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में गति और सुविधा जैसे बड़े लाभ हैं। सरकार चाहती है कि ऐसी कंपनियां देश के लोगों की सेवा करें।

पीयूष गोयल ने दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की भारत में एक अरब डॉलर के निवेश की घोषणा पर पिछले दिनों सवाल उठाते हुए कहा था कि अमेरिकी कंपनी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रही है, बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रही है। उन्होंने कहा था कि भारत में अमेजन को हुआ भारी घाटा असल में बाजार बिगाड़ने वाली बेहद कम कीमतों पर उत्पादों की बिक्री के तौर-तरीकों को बयां करता है लेकिन यह भारत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसका असर करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेताओं पर पड़ता है।

फास्टैग में बैलेंस का झंझट खत्म, अब टोल प्लाजा पर नहीं रुकेगी गाड़ी

फास्टैग और एनसीएमसी को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल किया गया

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों में बदलाव करके फास्टैग में बैलेंस कम होने के झंझट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आरबीआई के इस नए नियम की वजह से अब बैलेंस कम होने के कारण टोल प्लाजा पर गाड़ियों के रुकने की आशंका खत्म हो जाएगी और गाड़ियां फर्राटे से टोल प्लाजा को पार कर जाएंगी।

आरबीआई की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया है। ऐसा हो जाने से इन दोनों पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में निर्धारित लिमिट से पैसा कम होते ही ग्राहक के बैंक अकाउंट से जरूरत के मुताबिक पैसा खुद इन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा। इसका एक फायदा ये भी होगा कि अब ग्राहकों को बार-बार अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से फास्टैग रिचार्ज करने का झंझट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

आपको बता दें कि ई-मैंडेट फ्रेमवर्क को 2019 में तैयार किया गया था। इस फ्रेमवर्क को तैयार करने का मूल उद्देश्य ग्राहकों को उनके खाते से होने वाली पैसे की निकासी की जानकारी देकर उनके हितों की रक्षा करना था।

भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत पेमेंट की कोई पहले से निर्धारित या तय समय सीमा नहीं होती है। ऐसे में इन दोनों को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल कर लेने से बिना किसी निश्चित तय समय सीमा के पैसे खाते से निकल कर खुद ही इन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में क्रेडिट हो जाएंगे। इसके लिए ग्राहकों को प्री-डेबिट नोटिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसके पहले ग्राहकों को अपने खाते से पैसे डेबिट करने के लिए कम से कम 24 घंटा पहले प्री-डेबिट नोटिफिकेशन भेजना पड़ता था।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 से 7 जून को हुई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में ही फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करने की घोषणा की थी। इसके तहत रिकरिंग पेमेंट्स को भी शामिल करने की बात कही गई थी। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि देश में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और फास्टैग जैसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का चलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग को और सुविधाजनक बनाने की कोशिश लगातार चल रही है।

पहले फास्टैग या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के वॉलेट में पैसे जमा करना पड़ता था लेकिन वॉलेट में पैसे कम हो जाने पर ग्राहकों को पेमेंट करने में परेशानी होती थी। इसीलिए अब नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के जरिए जरूरत पड़ने पर खुद ही ग्राहकों के खाते के जरिए रिचार्ज हो जाएंगे।

उम्मीद है कि कबड्डी 2036 ओलंपिक का हिस्सा होगा : पोलैंड कबड्डी महासंघ अध्यक्ष स्पिज़्को

वारसॉ।
पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष मिशल स्पिज़्को को उम्मीद है कि कबड्डी ओलंपिक 2036 का हिस्सा होगा। मिशल स्पिज़्को ने यह भी उम्मीद जताई कि पीएम मोदी को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत पर दबाव डालना चाहिए और इस टूर्नामेंट में कबड्डी जैसे स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। कबड्डी के माध्यम से भारत और पोलैंड के बीच संबंध के बारे में बात करने के एक दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारसॉ में पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष मिशल स्पिज़्को और इसके बोर्ड सदस्य अन्ना कलबार्स्की से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद स्पिज़्को ने कहा, मैंने उनसे बहुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस की। उन्हें इस बात पर बहुत गर्व था कि अहमदाबाद में स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, क्योंकि वे गुजरात से हैं और इसी स्टेडियम में मैंने 2016 में अहमदाबाद में हुए विश्व कप के दौरान खेला था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का इस पद पर होना, भारत को हर खेल में मजबूत बनाने का एक शानदार अवसर है। भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए प्रयास करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कबड्डी इस ओलंपिक में शामिल होगी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड में कबड्डी को आगे बढ़ाने और यूरोप में खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके समर्पण के लिए स्पिज़्को और कलबार्स्की की सराहना की। उन्होंने भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में खेलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। इससे पहले, वारसॉ में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोलैंड और भारतीयों का कबड्डी के माध्यम से भी संबंध है।

प्रधानमंत्री ने कहा, आप जानते हैं कि भारत के हर गांव में कबड्डी खेली जाती है। यह खेल भारत से पोलैंड पहुंचा और पोलैंड के लोगों ने कबड्डी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पोलैंड लगातार दो वर्षों से यूरोपीय कबड्डी चैंपियन रहा है। मुझे बताया गया है कि 24 अगस्त से फिर से कबड्डी चैंपियनशिप होने जा रही है और पहली बार पोलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है। मैं आपके माध्यम से पोलिश कबड्डी टीम को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय विविधता के साथ जीना जानते हैं और उसका जश्न मनाना भी जानते हैं। पोलैंड की पुरुष राष्ट्रीय टीम ने अहमदाबाद में 2016 कबड्डी विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया। उनका शानदार पल तब आया जब उन्होंने प्रारंभिक ग्रुप मैच में तत्कालीन विश्व चैंपियन ईरान को हराया।

भारत की प्रो कबड्डी लीग में दो पोलिश खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। पोलिश स्टार डिफेंडर मिशल स्पिज़्को प्रो कबड्डी लीग में खेलने वाले पहले यूरोपीय खिलाड़ी थे, जब उन्हें 2015 में बेंगलुरु बुल्स ने खरीदा था। वह प्रतियोगिता के 2016 संस्करण में भी टीम के साथ थे। 2023 की खिलाड़ी नीलामी में बेंगलुरु बुल्स द्वारा चुने जाने के बाद पियोट्र पामुलक प्रो कबड्डी लीग में खेलने वाले दूसरे पोलिश खिलाड़ी बन गए।

न्यूज ब्रीफ

लुसाने डायमंड लीग: भाला फेंक फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा

नई दिल्ली। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके लुसाने डायमंड लीग में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर का शानदार फाइनल थ्रो करके शीर्ष स्थान हासिल किया। नीरज ने रात के अधिकांश समय 83 मीटर की रेंज में थ्रो करने के बाद, पांचवें और छठे प्रयास में दो क्लच थ्रो कर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शीर्ष दो में रहने के रिकॉर्ड को बरकरार रखा। 26 वर्षीय नीरज ने 82.10 मीटर, 83.21 मीटर और 83.13 मीटर की थ्रो के साथ शुरुआत करते हुए संघर्ष किया। इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचने में उनकी असमर्थता का मतलब था कि पीटर्स, जूलियन वेबर, आर्टुर फेलनर और रोडरिक डीन जेनकी जैसे खिलाड़ी उनसे आगे निकल गए। थ्रो के चौथे राउंड के अंत तक नीरज चौथे स्थान पर थे। इसके बाद मौजूदा विश्व चैंपियन ने पांचवें प्रयास में 85.58 मीटर थ्रो करके शीर्ष तीन में जगह बनाई, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह अंतिम थ्रो के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रह सकते हैं। पिछली बार नीरज शीर्ष तीन से बाहर 2018 में ज्यूरिख में डायमंड लीग में रहे थे। पीटर्स ने 90.61 मीटर का बड़ा थ्रो करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अंतिम के लिए बचाकर रखा, जो उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ और मीट रिकॉर्ड है। वेबर अपने अंतिम थ्रो में केवल 82.33 मीटर ही फेंक पाए। नीरज ने अंतिम थ्रो में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन भाला 90 मीटर के निशान से थोड़ा कम रह जाने के कारण वे निराश हो गए। उनका 89.49 मीटर का थ्रो उनके इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ और अब तक का उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, लेकिन वे एक बार फिर 90 मीटर के निशान से चूक गए।

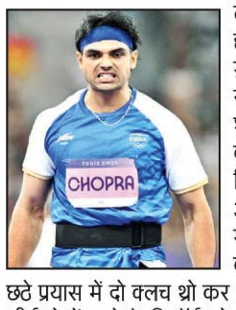

मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच दो सितंबर को लखनऊ में मुकाबला, सीएम योगी के पहुंचने की संभावना

नई दिल्ली। लखनऊ पहली बार देश के नामी फुटबाल क्लबों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच मैच की मेजबानी को तैयार है। परंपरागत प्रतिद्वंद्वियों के बीच होने वाला यह मुकाबला दो सितंबर को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि कृत्रिम रोशनी में होने वाले हाईवोल्टेज मैच के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। प्रदेश में फुटबाल के बढ़ावे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी मैच देखने के लिए आने की संभावना है। दस हजार से ज्यादा दर्शकों के स्टेडियम में उपस्थित होने की उम्मीद है। खेल निदेशक ने बताया कि अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी और उत्तर प्रदेश में फुटबाल को बढ़ावे को लेकर बातचीत हुई थी। एआईएफएफ ने मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच मैच के आयोजन का प्रस्ताव रखा और राज्य सरकार ने इसे मंजूर कर लिया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हाल ही में लगाई फ्लड लाइट का परीक्षण किया गया है और ड्रेसिंग रूम और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। दोनों टीमें एक सितंबर को लखनऊ पहुंच जाएंगी।

कुलदीप यादव ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेन वार्न को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। एक स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव ने हमेशा दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न को अपना आदर्श माना है और पहले भी अपनी गेंदबाजी शैली पर दिवंगत दिग्गज के महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में बात की है। शुक्रवार को भारतीय लेग स्पिनर ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाले संदेश के साथ अपने आदर्श को श्रद्धांजलि दी। कुलदीप ने इंस्टाग्राम पर लिखा, शेन की गेंदबाजी...हमेशा और हमेशा के लिए। अपने करियर के शुरुआती दौर में, कुलदीप एक तेज गेंदबाज के रूप में बड़े हुए और पाकिस्तान के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज वसीम अकरम एक युवा के रूप में उनके आदर्श थे। जब उनके कोच ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की नकल करने की सलाह दी, तो उन्होंने स्पिन गेंदबाजी करना शुरू कर दिया। आईसीसी रिव्यू के एक पुराने एपिसोड में, कुलदीप ने बताया था कि कैसे वॉर्न पिछले साल अपनी मृत्यु से पहले अक्सर उन्हें स्पिन गेंदबाजी के बारे में सलाह देते थे। अब भी, कुलदीप कुछ अतिरिक्त प्रेरणा पाने के लिए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर के पुराने वीडियो देखते हैं। आईसीसी रिव्यू में कुलदीप के हवाले से कहा गया, अगर मुझे कोई संदेह है (मैं कैसे गेंदबाजी कर रहा हूं), तो मैं उनके पुराने एक्शन को देखता हूं। मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया और उनका अच्छा दोस्त रहा।

भारतीय मूल की तीन खिलाड़ी शामिल

ऑस्ट्रेलिया ने त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए अंडर-19 महिला टीम घोषित की

मेलबर्न।
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने आगामी महिला अंडर-19 त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए टीम का ऐलान कर दिया है, जो 19 सितंबर से ब्रिसबेन में शुरू होगी। समारा डुल्विन और हसरत गिल के साथ रिब्या स्यान को भी टीम में शामिल किया गया है।

युवा चयन पैनल ने ब्रिसबेन और गोल्ड कोस्ट में होने वाली ट्राई सीरीज के लिए प्रत्येक प्रारूप (टी20 और 50 ओवर) के लिए 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस्टन बीम्स को टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। इस मल्टी-फॉर्मेट सीरीज में भाग लेने वाली अन्य दो टीमें न्यूजीलैंड और श्रीलंका हैं।

इस 14 दिवसीय ट्राई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया चार टी20 और दो वन-डे मैच खेलेगा। इस टीम में भारतीय मूल की तीन होनहार प्रतिभाएं रिब्या स्यान, समारा डुलविन और हसरत गिल शामिल हैं। उनका शामिल होना ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बढ़ती विविधता और भारतीय मूल के खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

ये हैं भारतीय मूल की तीन खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 महिला - टी20 टीम

बोनी बेरी, काओइमहे ब्रे, एला ब्रिस्को, मैगी क्लार्क, समारा डुल्विन, लुसी फिन, हसरत गिल, लुसी हैमिल्टन, एमी हंटर, एलेनोर लारोसा, इनेस मैककॉन, रिब्या स्यान, टेगन विलियमसन, एलिजाबेथ वर्थली, हेले ज़ौच।

ऑस्ट्रेलियाई अंडर-19 महिला - 50 ओवर टीम

बोनी बेरी, काओइमहे ब्रे, एला ब्रिस्को, मैगी क्लार्क, समारा डुल्विन, लुसी फिन, हसरत गिल, एमी हंटर, एलेनोर लारोसा, इनेस मैककॉन, जूलियट मॉर्टन (एनएसडब्ल्यू) रिब्या स्यान, टेगन विलियमसन, एलिजाबेथ वर्थली, हेले ज़ौच।

डीपीएल: ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने सुपरस्टार्स को हराया

नई दिल्ली। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जा रही दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) टी20 में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को सात विकेट से हरा दिया। इस मैच में 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, ईस्ट दिल्ली राइडर्स की ओर से सलामी बल्लेबाजों अनुज रावत और सुजल सिंह ने शानदार शुरुआत कर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। रावत ने 34 रन जबकि सुजल ने 63 रन बनाये। वहीं कप्तान हिम्मत सिंह ने 29 रन बनाये। सुजल ने केवल 19 गेंदों पर ही अर्धशतक लगा दिया। इनके आउट होने के बाद

हार्दिक शर्मा ने 38 रनों जबकि समर्थ ने 24 रन बनाए। वहीं इससे पहले ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने टॉस जीतकर सुपरस्टार्स को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। सुपरस्टार्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसके सलामी बल्लेबाज सार्थक दो रन ही बना पाये। इसके बाद कप्तान आयुष बदौनी ने प्रियांश के साथ 67 रन की साझेदारी कर पारी संभाली।

बदौनी ने 32 रनों रन बनाये। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 20 ओवरों में सात विकेट पर 191 रन बनाये। ईस्ट दिल्ली राइडर्स की ओर से मयंक रावत और हर्ष त्यागी ने दो-दो विकेट लिए।

बीबीएल 2024 : ब्रिसबेन हीट में वापसी कर सकते हैं पॉल वाल्टर

मेलबर्न।
पिछले सत्र में ब्रिसबेन हीट की बिग बैश लीग (बीबीएल) खिताबी सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले ऑलराउंडर पॉल वाल्टर अगले महीने के ड्राफ्ट के लिए नामांकन के नवीनतम बैच में शामिल होने के बाद प्रतियोगिता में वापसी कर सकते हैं।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज वाल्टर ने पिछले संस्करण में हीट के लिए 17 विकेट लिए थे और उन्हें आठ मुख्य कोचों द्वारा वोट किए गए टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में नामित किया गया था।

हीट के पास वाल्टर को रिटेन करने के अधिकार हैं। एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि वह फाइनल सहित पूरी तरह से उपलब्ध है और माइकल नेसर, जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन और स्पिन ट्विन्स मैट कुहनेमैन और मिशेल स्वेपसन सहित उनके विविध आक्रमण को पूरक बनाने के बाद वह फिर से उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं।

शुक्रवार को जारी की गई सूची में इंग्लिश क्रिकेटरों का दबदबा रहा, हालांकि अधिकांश केवल छह से नौ खेलों के लिए ही उपलब्ध हैं। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेलनी है जो बीबीएल शुरू होने के तीन दिन बाद खत्म होगी और फिर अगले साल 22 जनवरी से भारत का सीमित ओवरों का दौरा शुरू होगा। काफी संख्या में खिलाड़ियों के पास आईएलटी20 या एसए20 डील भी हैं।

हालांकि, ओली स्टोन, डैन लॉरेंस, जॉर्डन कॉक्स और जो क्लार्क सहित कुछ खिलाड़ियों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। लेगस्पिनर रेहान अहमद, जिन्हें पिछले सीजन में सिडनी सिक्सर्स ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन जब उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए चुना गया तो उन्होंने नाम वापस ले लिया, उन्होंने फिर से नामांकन किया है।

पाकिस्तान के ऑलराउंडर इमाद वसीम, जिनके लिए मेलबर्न स्टार्स के पास रिटेंशन अधिकार हैं, पूरी तरह से उपलब्ध हैं, साथ ही पिछले सीजन में सिडनी थंडर के लिए खेलने वाले तेज गेंदबाज जमान खान भी पूरी तरह से उपलब्ध हैं।

इंग्लैंड के खिलाड़ियों का भी डब्ल्यूबीबीएल के नवीनतम नामांकन में मजबूत प्रतिनिधित्व है। पिछले हफ्ते हंड्रेड फाइनल में निर्णायक भूमिका निभाने वाली और कप्तान हीथर नाइट की प्रशंसा पाने वाली डैनी गिब्सन ने पिछले सीजन में चैंपियन एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए मध्य क्रम में 147.43 की औसत से रन बनाए और दस विकेट लिए। उन्हें फिलहाल पूरी तरह से उपलब्ध नहीं माना जा रहा है, हालांकि इंग्लैंड को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है, जो डब्ल्यूबीबीएल फाइनल के साथ ओवरलैप होती है।

डूरंड कप क्वार्टर फाइनल : मोहन बागान का पीएफसी से मुकाबला; बेंगलुरु के सामने केरला

नई दिल्ली।
इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की चार टीमें - गत चैंपियन मोहन बागान एसजी, पंजाब एफसी (पीएफसी), बेंगलुरु एफसी और केरला ब्लास्टर्स एफसी - शुक्रवार को डुरंड कप 2024 के अंतिम दो सेमीफाइनल स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी और शिलांग लाजोंग एफसी पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर चुके हैं, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी ने भारतीय सेना फुटबॉल टीम को हराया और शिलांग लाजोंग एफसी ने ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ आश्चर्यजनक जीत हासिल की।

आईएसएल की मीडिया विज्ञप्ति के अनुसार, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी बनाम शिलांग लाजोंग एफसी मैच का विजेता फाइनल में पहुंचेगा। अब ध्यान शेष क्वार्टर फाइनल मुकाबलों पर केंद्रित है। मोहन बागान एसजी का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा, जबकि बेंगलुरु एफसी का सामना केरला ब्लास्टर्स एफसी से होगा। टूर्नामेंट के तीसरे नॉकआउट गेम में पुराने और नए का मिश्रण होगा क्योंकि मोहन बागान एसजी का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा।

बेंगलुरु एफसी की टीम साल्ट लेक स्टेडियम में केरला ब्लास्टर्स की मेज़बानी में अपने अपराजित रिकॉर्ड को परखने उतरेगी। केरला ब्लास्टर्स अपने ग्रुप में शीर्ष पर रही, जिसमें सीआईएसएफ प्रोटेक्टर्स, पंजाब एफसी और मुंबई सिटी शामिल थे। दूसरी ओर, बेंगलुरु एफसी ने इंडियन नेवी, इंटर काशी और मोहम्मडन एससी के खिलाफ़ कड़ी टक्कर के बाद अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की की।

दोनों टीमें डिफेंसिव रूप से मजबूत रही हैं और दोनों ने मिलकर केवल तीन गोल खाए हैं। आईएसएल के अनुसार, बेंगलुरु एफसी ने तीन मैचों में 10 गोल किए हैं और 9 अंक अर्जित किए हैं, जबकि केरल ब्लास्टर्स ने समान मैचों में 16 बार गोल किया है।

उपलब्धि : जिम्बाब्वे को 2026 से आईसीसी महिला वनडे चैम्पियनशिप में किया जाएगा शामिल

नई दिल्ली।
आईसीसी महिला चैंपियनशिप के अगले संस्करण में टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है, जिसमें जिम्बाब्वे की महिला टीम 2026-29 संस्करण में अन्य पूर्ण सदस्य टीमों के साथ शामिल होगी।

आईसीसी ने इस महीने की शुरुआत में संबंधित सदस्य बोर्डों को पुष्टि की थी कि आईसीसी बहु-वर्षीय महिला वनडे प्रतियोगिता, जो आईसीसी महिला विश्व कप के लिए सीधे योग्यता मार्ग के रूप में कार्य करती है, 2022-25 चक्र के लिए आयरलैंड और बांग्लादेश को जोड़ने के बाद फिर से विस्तारित होगी।

उल्लेखनीय है कि महिला चैंपियनशिप को पहली बार 2014 में 8 टीमों की प्रतियोगिता के रूप में पेश किया गया था, जिसमें पहले दो चक्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज शामिल थे, इस टूर्नामेंट ने 2017 और 2022 महिला विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग मार्ग के रूप में काम किया था। प्रतियोगिता के पहले दो संस्करणों में, जिनमें से दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, आठ टीमों ने 2.5 वर्षों के दौरान अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी के साथ घर पर या बाहर 3-मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेली (हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच मैच नहीं हुए) जिसमें शीर्ष तीन फिनिशर और विश्व कप मेजबान ने सीधे विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया।

2022-25 चक्र में प्रतियोगिता का विस्तार दस टीमों तक हुआ, जिसमें आयरलैंड और बांग्लादेश को 9वें और 10वें स्थान पर रखा गया। मौजूदा संस्करण में टीमें घर या बाहर आठ सीरीज़ खेलेंगी, जिसमें शीर्ष पांच फिनिशर और मेजबान भारत 2025 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगे, जबकि शेष चार टीमें 2025 महिला विश्व कप क्वालीफायर में महिला वनडे रैंकिंग तालिका में अगली सर्वश्रेष्ठ रैंक वाली टीमों (वर्तमान में थाईलैंड और स्कॉटलैंड) के खिलाफ़ मुकाबला करेंगी, ताकि शेष दो क्वालिफिकेशन स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा की जा सके।

आने वाले चक्र के लिए जिम्बाब्वे को शामिल करने की योजना का मतलब यह होगा कि अफगानिस्तान को छोड़कर आईसीसी के सभी पूर्ण सदस्य, जो महिला टीम नहीं उतारते हैं, लीग के अगले संस्करण में शामिल होंगे।

जिम्बाब्वे, जिन्हें 2021 में महिला वनडे का दर्जा दिया गया था, वर्तमान में महिला वनडे तालिका में पांच एसोसिएट महिला वनडे टीमों में से तीन - नीदरलैंड (13वें), स्कॉटलैंड (12वें) और थाईलैंड (9वें) से पीछे 14वें स्थान पर है।

राष्ट्रीय खेल परिषद ने बीसीबी निदेशकों की नियुक्ति पर रुख किया साफ

ढाका।
राष्ट्रीय खेल परिषद (एनएससी) ने शुक्रवार को स्पष्ट किया है कि उन्होंने न्यायशास्त्र के दर्शन के आधार पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के निदेशक के रूप में दो नए प्रतिनिधियों को नामित किया है। इससे पहले, एनएससी ने जलाल यूनुस और सज्जादुल आलम को बीसीबी निदेशक के रूप में नामित किया था।

क्रिकबज के अनुसार, संविधान एनएससी को बोर्ड में पांच पार्षद रखने की अनुमति देता है, जिसमें से दो को 25 सदस्यीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। पिछली बोर्ड बैठक में जहां फारुक को बीसीबी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जलाल और सज्जादुल दोनों को क्रमशः नजमुल आबेदीन और फारुक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। भ्रम की स्थिति तब पैदा हुई जब जलाल द्वारा नजमुल आबेदीन के लिए रास्ता बनाने के लिए ऐसा करने का फैसला करने के बाद सज्जादुल ने बीसीबी निदेशक के रूप में अपने पद से इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया।

सज्जादुल ने मीडिया से दावा किया कि जिस तरह से एनएससी ने उनसे पार्षद पद और बीसीबी निदेशक पद छीना, वह बोर्ड के मामलों में सीधे हस्तक्षेप के समान है।

सज्जादुल ने डेली स्टार से बातचीत में कहा, मैं बेहद हैरान और निराश हूं। एनएससी ने जो किया, वह बोर्ड के कामकाज में सीधे हस्तक्षेप के समान है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एनएससी से किसी ने भी मुझसे सीधे संवाद नहीं किया। बीसीबी के सीईओ ने नए पार्षद की नियुक्ति के बारे में एनएससी नोटिस की एक प्रति मुझे व्हाट्सएप पर भेजी। यह मुझे (मंत्रालय में) बैठक के बाद शाम 7 बजे भेजी गई।

एनएससी ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जलाल और सज्जादुल के स्थान पर फारुक और नजमुल को नामित करने के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया क्योंकि निदेशकों से इस्तीफा देने के एनएससी के अनुरोध के पीछे का तर्क स्पष्ट नहीं है, जिससे एनएससी के मामलों में सरकारी हस्तक्षेप के बारे में संभावित चिंताएं बढ़ गई हैं।

एनएससी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के संविधान के अनुच्छेद 9.3.2 के अनुसार, मोहम्मद जलाल यूनुस ने 19 अगस्त, 2024 को राष्ट्रीय खेल परिषद द्वारा पार्षद श्रेणी में पहले से नामित पांच प्रतिनिधियों में से इस्तीफा दे दिया, और नजमुल आबेदीन फहीम को खेल परिषद द्वारा नामित एक रिक्त पद के लिए राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया।

दूसरी ओर, फारुक अहमद और नजमुल आबेदीन फहीम को संविधान के अनुच्छेद 13.2 खंड 4 के अनुसार निदेशक श्रेणी में राष्ट्रीय खेल परिषद द्वारा नामित किया गया है, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की जा रही है। इस तरह के नामांकन न्यायशास्त्र के दर्शन के आधार पर प्रचलित नियमों के अत्यंत सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग के साथ किए जाते हैं।

सरकार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सहित सभी महासंघों/संघों की गतिविधियों को सुचारू, कुशल, सक्रिय और निर्बाध रखने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रगति में सभी तिमाहियों का सहयोग मांगा जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 13.2 खंड 4 में कहा गया है कि एनएससी तीन पार्षद श्रेणियों में से किसी से भी बीसीबी निदेशक को नामित कर सकता है। नजमुल और फारुक दोनों ही श्रेणी तीन के तहत पार्षद हैं।

गृह कलह को शांत करेंगे ये उपाय

गृह कलह के यूं तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ज्योतिष एवं वास्तु की दृष्टि से गृह कलह ग्रहों के दोषपूर्ण या अशुभ दशा होने अथवा भवन में एक या अनेक वास्तु दोष होने से भी गृह कलह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ज्योतिष में गृह कलह का निवारण संभावित गृह कलह के निवारण के लिए वर-कन्या के विवाह से पहले अगर सही तरीके से कुंडली में गुणों का मिलान करवा लिया जाये तो अच्छा रहता है। फलित ज्योतिष के अनुसार मंगल, शनि और राहु ग्रहों के विभिन्न भावों में बैठे होने से उन भावों से सम्बंधित रिश्तों में मतभेद और कलह देखा जा सकता है। इसके निवारण के लिए उस दोषपूर्ण ग्रह से सम्बंधित वस्तुओं का दान करने, मंत्र जप, पूजा-पाठ, रत्न या रुद्राक्ष धारण करने से लाभ मिलता है।

» घर-परिवार में सुख-शांति और प्रेम भाव बनाए रखने के लिए भोजन बनाते समय सबसे पहली रोटी के बराबर चार टुकड़े करके एक गाय को, दूसरा काले कुत्ते को, तीसरा कौए को खिलाना चाहिए तथा चौथा टुका किसी चौराहे पर रख देना चाहिए। घर के पूजा घर में अशोक के सात पत्ते रखें। उनके मुरझाने पर तत्काल नए पत्ते रखकर पुराने पत्ते पीपल के वृक्ष नीचे रखने से गृह कलह दूर होने लगता है।

» अगर परिवार में कलह के कारण मानसिक तनाव और परेशानी हो रही हो तो एक पतंग पर अपनी परेशानी लिखकर सात दिनों तक उसे उड़ाकर छोड़ देने से समस्या का समाधान होता है। पति और पत्नी के बीच झगड़ा होता हो तो घर में विधि-विधान से स्फटिक के शिवलिंग स्थापित करके इकतालीस दिनों तक उस पर गंगा जल और बेल पत्र चढ़ाएं तथा '? नम: शिवशक्तिस्वरूपाय मम गृहे शांति कुरु कुरु स्वाहा' मंत्र का ग्यारह माला जप करने से झगड़ा शांत होने लगता है।

» छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवादों को रोकने के लिए

केवल सोमवार अथवा शनिवार के दिन गेहूं पिसवाते समय एक सौ ग्राम काले चने भी मिलवाएं। इस आटे की रोटी खाने से भी गृह कलह दूर होता है।

» यदि चंद्र ग्रह के अशुभ या दूषित होने से परिवार में अक्सर कलह रहती है तो इसके लिए रविवार रात में अपने सिरहाने स्टील या चांदी के एक गिलास में गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध रखें और प्रात:काल उसे बबूल के पेड़ पर चढ़ा दें।

» इन उपायों के साथ-साथ घर में बबूल की धूनी देने, गणेश एवं पार्वती की आराधना करने, चींटियों को शक्कर डालने, पूर्व दिशा की ओर सिरहाना करके सोने, हनुमान जी की उपासना करने, सेंधा नमक मिश्रित पानी से घर में पोछा लगाने आदि से भी गृह कलह दूर होकर शांति बनी रहती है।

» वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अगर भवन में कोई वास्तु दोष है तो गृह कलह संभव है। इसके लिए घर के प्रवेश द्वार के सामने यदि कोई पेड़ नुकीला कोना, मंदिर की छाया, हेंड पंप आदि हैं तो उन्हें या तो हटवा दें अथवा अपने द्वार को सरकवा दें।

» घर के अंदर युद्ध, डूबती नाव, जंगली जानवर, त्रिशूल, भाले आदि के चित्र अथवा प्रतिमा रखने से बचें। बेडरूम में दर्पण ऐसी जगह लगाएं जहां से सोते समय अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे।

» अगर घर की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ है तो उसे तत्काल ठीक कराएं। भवन में किचन उत्तर-पश्चिम दिशा में न रखें अन्यथा गृह कलह होने की संभावना बनी रहेगी।

मोटापे से बढ़ जाता है लिवर का खतरा

मोटापे से किशोरों में लिवर संबंधी गंभीर बीमारी या उम्र बढ़ने के साथ यकृत कैंसर के होने का खतरा ज्यादा रहता है। शोधकर्ता ने अपने निष्कर्ष में बताया कि सामान्य वजन वाले पुरुषों की तुलना में मोटापाग्रस्त पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ लिवर की बीमारी होने की संभावना दोगुने से ज्यादा होती है। मोटापा और टाइप 2 मधुमेह वाले पुरुषों में समान्य लोगों की तुलना में लिवर की समस्या होने की संभावना तीन गुनी ज्यादा होती है।

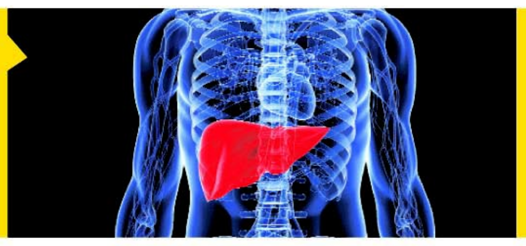

बीयर बुरी नहीं आपकी सोच है बुरी

बीयर पीना या न पीना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन, हम यहां आपको बता रहे हैं कि ऐसे कारण जिन्हें पढ़कर आपको ज्ञात होगा कि अगर इसका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए तो बीयर आपके लिए क्यों नुकसानदेह नहीं है। याद रखें, हम आपको बीयर पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे। अगर आप शराब नहीं पीते या आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

बीयर पीने वाले लंबा जीते हैं

संतुलित मात्रा में बीयर पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। हां, ज्यादा मात्रा जरूर आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। अगर आप ज्यादा पीते हैं, तो आपको कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप बिलकुल ही नहीं पीते, तो यह भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। कई शोध यह बता चुके हैं कि संतुलित मात्रा में पीने वाले, ज्यादा पीने वालों या बिलकुल ही न पीने वालों की अपेक्षा अधिक लंबा जीवन जीते हैं। बीयर संतुलित मात्रा में पीने के लिए उपयुक्त है। इसमें एल्कोहल की मात्रा वाइन और व्हिस्की आदि की अपेक्षा कम होती है।

कुदरती होती है बीयर

कुछ लोग मानते हैं कि बीयर में कई प्रिजरवेटिव मिलाये जाते हैं। लेकिन, सच्चाई यह है कि बीयर ओरेंज जूस जितनी ही कुदरती होती है। और कई मामलों में उनसे भी ज्यादा। क्योंकि पैक्ड ओरेंज जूस और मिलावटी दूध के नुकसानों के बारे में हम जानते ही हैं। बीयर को प्रिजरवेटिव की जरूरत नहीं होती। इसमें एल्कोहल और होप्स होता है। ये दोनों ही कुदरती प्रिजरवेटिव हैं। बीयर को बनाने की प्रक्रिया ब्रेड जैसी ही है। इसे भी पकाया और किण्वित किया जाता है।

कोलेस्ट्रॉल स्तर में सुधार

बीयर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सुधारती है। संतुलित मात्रा में बीयर का सेवन करना शरीर में गुड और बेड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करती है। बीयर शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है।

विटामिन बी होता है भरपूर

बीयर और खासकर अनफिल्टर या लाइट बीयर, बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है। बीयर में विटामिन बी के सभी रूप उच्च स्तर में होते हैं। इसमें फॉलिक एसिड होता है जो हार्ट अटैक से बचाने में मददगार होता है। बीयर में घुलनशील फाइबर होता है, जो आपको रोजमर्रा के काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। इसके साथ ही यह फाइबर हमारे शरीर में जमा अतिरिक्त वसा और गंदगी को निकालने में मदद करता है।

पानी से अधिक सुरक्षित है बीयर

अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हैं, जहां आपको पानी न पीने की सलाह दी जाती है, तो आप बीयर पी सकते हैं। यह ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। बीयर को उबालकर बनाया जाता है। इसके बाद सीलबंद होने तक इसमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। यदि यह स्वच्छ न होती, तो शायद इसे बेच पाना भी असंभव होता। अगर बीयर बुरी भी हो, तो उसमें कोई जानलेवा बैक्टीरिया नहीं होता। तो, आप बेफिक्र होकर बीयर पी सकते हैं। यह पानी से सुरक्षित होती है।

अटैक से बचाये

रेड वाइन के अलावा डार्क बीयर में काफी अधिक मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं। वाइन अन्य एल्कोहोलिक पेय पदार्थों के मुकाबले अधिक फायदेमंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना तीन ड्रिंक पीना दिल की बीमारियों के खतरे को 24.7 फीसदी तक कम कर सकती है।

कैंसर से लड़े

बीयर का सबसे कमाल का फायदा यह है कि यह कैंसर से लड़ने में मददगार होती है। बीयर बनाने में इस्तेमाल होने वाले पौधे होप्स में एक्सनथोहूमोल पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में मदद करता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट केवल और केवल बीयर में ही मिलता है।

बीयर से पेट नहीं निकलता

पेट निकलने और बीयर के सेवन के बीच कोई समानता नहीं है। आमतौर पर माना जाता है कि बीयर पीने वाले, बीयर न पीने वालों की अपेक्षा अधिक मोटे होते हैं। कई शोध तो यह दावा करते हैं कि संतुलित मात्रा में बीयर पीने वाले लोगों का पेट और वजन बीयर न पीने वालों की अपेक्षा कम होता है।

कैलोरी की मात्रा है कम

बीयर में कैलोरी बहुत कम होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। वसा या कोलेस्ट्रॉल बिलकुल नहीं होती। लगभग 12 औंस बीयर में 156 कैलोरी के साथ 14 एमजी सोड़ियम, 0 वसा, 12.6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 प्रतिशत कैल्शियम पाया जाता है।

किडनी में स्टोन नहीं होता

शोध के अनुसार बीयर पीने से पथरी होने का खतरा कम हो जाता है। 40 % बीयर पीने वाले लोगों में किडनी स्टोन होने का खतरा उन लोगों के मुकाबले काफी घट गया था। जो बीयर नहीं पीते थे। हालांकि शोधकर्ता यह निर्धारित नहीं कर सके। कि बीयर में ऐसी कौन सी चीज शामिल थी। जिसकी वजह से यह हो सका।किड़नी स्टोन में असहनीय दर्द होता है।

जींस खरीदते वक्त बिना दुकानदार की बातों में आएं इन बातों का रखे विशेष ख्याल

हममें से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपना अधिकांश समय जींस पहने-पहने ही बिताते हैं. जींस की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के समय में ये हर किसी की आलमारी का हिस्सा बन चुकी है. इसे पहनना काफी आरामदेह है।अगर आप जींस का इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो आपको एक ऐसी जींस चाहिए, जो कंफर्टेबल भी हो साथ ही टिकाऊ भी। इन सब के साथ अगर जींस का लुक अच्छा हो तो यह आपके आउटफिट में चार-चांद लगा सकता है। परफेक्ट जींस खरीदना एक चैलेंज जैसा ही है। ये टिप्स आपको एक परफेक्ट जींस खरीदने में मदद करेंगे।

फैब्रिक पर ध्यान दें

जींस खरीदने से पहले फैब्रिक को अच्छी तरह से छूकर देख लें। इससे आपको फैब्रिक की क्वालिटी का पता चल जाएगा। फैब्रिक की क्वालिटी पता करने में जल्दबाजी ना करें। जींस खरीदने से पहले उसके देश और ब्रांड के बारे में जान लें। वैसे जर्मनी के जींस की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है।

कॉटन मिक्स हो

जीन्स खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें 80 से 100 प्रतिशत तक कॉटन मिक्स हो। ऐसी जीन्स की फिटिंग काफी अच्छी होती है। कई छोटे-मोटे ब्रांड कुछ और फैब्रिक को भी जीन्स के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे स्पैंडेक्स, जो देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन फिटिंग में बेकार होती है। अगर जींस लिनेन मिक्स भी हो तो भी एक परफेक्ट फिट देती है।

कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें

हमेशा एक जैसी जींस मत खरीदिये। कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया ट्राय करें। ज्यादातर लोग एक ही तरह की जींस पहनते हैं। जबकि ये गलत है। इससे साइज का पता नहीं चलता। जबकि हर उम्र में शरीर का साइज बदलता है तो ऐसे में जरूरी है कि जींस का साइज हमेशा बदलते रहें।

स्टाइल और डिजाइन

समय के साथ कई स्टाइल्स ट्रेंड बन जाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे स्टाइल्स जो आपको हमेशा इग्नोर ही करने चाहिए। जैसे आपकी बैक पॉकेट डिजाइन वाली न हो, ड्रमाटिक वॉश पैटर्न न हो। साथ ही ऑवर डिजाइन न हो। डिजाइन सिंपल हो और उसका लुक क्लासिक हो।

ऑकेजन का रखें ध्यान

जींस चुनने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप किस उद्देश्य के लिए खरीदारी कर रहे हैं। ऑफिस में कैजुअल थीम के लिए या फिर दोस्तों के साथ डे-आउट के लिए। अगर आप ऑफिस के लिए चुन रहे हैं तो आपकी जींस सिंपल और क्लासी होनी चाहिए। अगर दोस्तों के साथ डे-आउट पर जा रहे हों तो आप नैरो फिट जींस भी ट्राई कर सकते हैं।

मस्तिष्क के दोनों भागों को सक्रिय करने के तरीके

एक अवधारणा रही है कि मनुष्य अपने दिमाग का प्रयोग शत-प्रतिशत नहीं कर पाता है। लेकिन एक सिद्धांत की मानें तो मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दोनों भाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तथा आपस में लगभग 200 मिलियन नर्व फाइबर्स से जुड़ होते हैं, इसे कारपस केलोसम' नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य है मस्तिष्क के एक भाग से दूसरे भाग को यह कहना है कि वह क्या कर रहा है। मस्तिष्क के ये दोनों भाग देखने में एक-दूसरे के प्रतिबिम्ब लगते हैं, परन्तु उनके कार्यों में काफी अंतर होता है। सामान्यतया मस्तिष्क के दोनों अंग सक्रिय नहीं होते हैं, इसे सक्रिय करने के लिए ये तरीके आजमायें।

शांत और स्थिर मन

मस्तिष्क के दांयें और बांयें हिस्सों के बीच सामंजस्य बढाने का एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर कोई इंसान अपने स्थूल शरीर को शांत और स्थिर रख सकता है, तो शरीर की निश्चलता की इस स्थिति में मस्तिष्क एक बड़े पैमाने पर जुड़ जाता है। इससे किसी भी चीज को जल्दी और आसानी से सीखा जा सकता है।

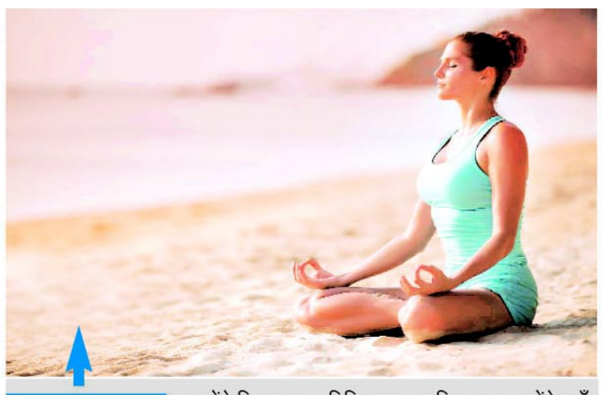

सिल्वा ध्यान

उन्होंने सिल्वा ध्यान विधि का प्रचार किया था। उन्होंने बाएँ हाथ से काम करने वालों को मस्तिष्क के बाएँ हिस्से पर चेतन मन को आँखें बंद करके पहुँचाने और एकाग्रता करने के लिए सचेत किया था। उसी प्रकार जो व्यक्ति दाहिने हाथ से कार्य करते हैं, उन्हें दाहिने मस्तिष्क के भाग पर चेतन मन को केंद्रित करके ध्यान करने की विधि बताई थी।

प्राणायाम

प्राणायाम करते समय दोनों स्वर (नाक के भाग) चलने स मस्तिष्क के दोनों भागों को प्राणवायु का संचार होने लगता है और मस्तिष्क के दोनों भाग समान रूप से उन्नत होते हैं। प्राणायाम में अनुलोम-विरोम, सूर्यभेदि प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एवं उज्जयी प्राणायाम मस्तिष्क के विकास में अत्यधिक मदद करते हैं।

ध्यान के फायदे

ध्यान से मस्तिष्क दोनों के भाग का संपूर्ण विकास होकर तनाव निर्माण करने वाले हार्मोंस कम बनते हैं और उपयुक्त हार्मोन्स जैसे मेलाटोनीन, सायटोसीन, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन का अधिक निर्माण होने से क्रियाशीलता, नूतन विचार, समस्याओं का हल, प्रेमभाव, समझने की शक्ति, कार्य करने की इच्छा आदि बढ़ने लगती है।

ये हैं ग्रीन-टी पीने का सही समय

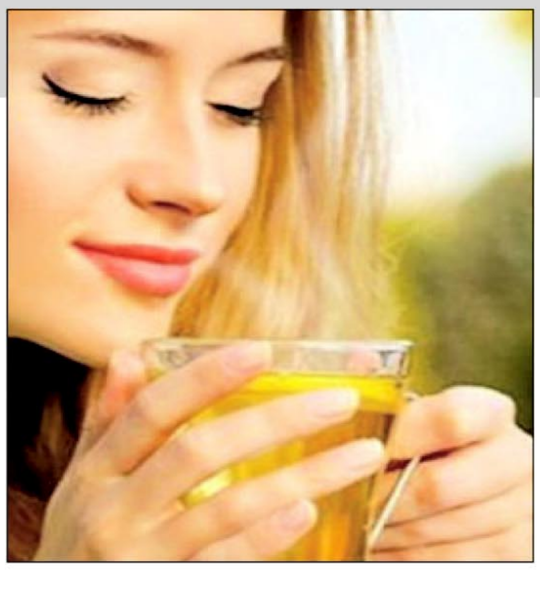

फिट रहने के लिए कई लोग ग्रीन-टी का सेवन करते हैं। यह शरीर की फिटनेस ही नहीं सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर का मोटापा कम करने में मदद करते हैं लेकिन कुछ लोग जल्दी पतले होने की चाह में दिन में कई बार इसका सेवन कर लेते हैं जिससे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इससे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है और पेट की भी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए ग्रीन-टी सही समय और उचित मात्र में पीएं जिससे सेहत को फायदा मिले।

सही समय ग्रीन-टी पीने का सही समयग्रीन-टी से शरीर को फायदा पहुंचाने के लिए इसको सही समय पर पीना बहुत जरूरी है। भोजन करने से 1 या 2 घंटे पहले ग्रीन-टी का सेवन करें।

खाली पेटसुबह खाली पेट न पियें ग्रीन-टी पीने से मोटापा कम होता है इसलिए कई लोग इसे खाली पेट पीना पसंद करते हैं जिससे चर्बी जल्दी कम हो लेकिन खाली पेट पीने से काफी नुकसान होता है। इसमें कैफिन होता है जिसे खाली पेट पीने से आंतों की कई समस्याएं हो जाती हैं।

गर्म पानी गर्म पानी

कुछ लोग ग्रीन-टी को आम चाय की तरह बना कर पीते हैं। इसमें दूध और शक्कर डालकर पीने से शरीर को कोई फायदा नहीं होता और न ही मोटापा कम होता है। इसके लिए हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें।

शहद जिस तरह गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से वजन कम होता है उसी तरह ग्रीन-टी में भी शहद मिलाकर पीएं। ग्रीन-टी से पेट की पाचन शक्ति ठीक रहती है और शहद से पेट की चर्बी जल्दी कम होती है। ऐसे में इन दोनों का साथ में सेवन करने से काफी फायदा होता है।

एक दिन में केवल 2-3 कप-एक दिन में केवल 2-3 कपखाने के तुरंत बाद कभी भी ग्रीन-टी का सेवन न करें। इसके अलावा दिन में कम से कम 2-3 कप ग्रीन-टी ही पीएं। इसके अधिक सेवन से लीवर को नुकसान होता है।

रेसिपी

मखाना चिक्की

सामग्री

मखाने - 100 ग्राम
घी - 200 ग्राम
चीनी - 500 ग्राम
दूध - 1 बड़ा चम्मच

विधि

सबसे पहले सारे मखानों को चार टुकड़ों में काट लीजिए। कड़ाही में घी डाल कर गर्म कीजिए। इसमें थोड़े-थोड़े मखाने डालकर हल्के गुलाबी होने तक तल कर निकाल लीजिए। सारे मखाने को ऐसे ही तल कर रख लीजिए। चाशनी बनाने के लिए कड़ाही में शक्कर और इसका एक तिहाइ पानी डालकर गर्म कर लें। शक्कर घुल जाने के बाद इसमें दूध डाल दीजिए। जब भूरे रंग के झाग ऊपर उठने लगे तो चम्मच की मदद से झाग को बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार गाढ़ी चाशनी तैयार कर लीजिए। अब इस चाशनी में तले हुए मखाने डालकर कलछी से चलाते हुए मिलाइये। इस मिश्रण को घी लगे हुए थाली में निकालकर फैला दीजिए। थोड़ी ही देर में ये जम जाता है। इसे टुकड़ों में काट तक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। इसे आप काफी दिनों तक रख सकते हैं।

दही अरबी

सामग्री

अरबी - 250 ग्राम, दही - 150 ग्राम (3/4 कप), तेल - 1-2 चम्मच, अजवायन - आधी छोटी चम्मच, हींग - 1-2 पिंच, हरी मिर्च - 2-3 (बारीक कतरी हुई), हल्दी पाउडर-एक चौथाई छोटी चम्मच, धनियां पाउडर - आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर - एक चौथाई छोटी चम्मच, नमक - स्वादानुसार, गरम मसाला - 1/4 छोटी चम्मच से कम, हरा धनियां - 1 एक बड़ा चम्मच

विधि

सबसे पहले अरबी को धो कर उबाल लीजिये। ठंडा करने के बाद इसे छील कर आधा इंच मोटे और गोल टुकड़ों में काट लीजिए। अब दही को अलग से फेंट लीजिए। इस एक बर्तन में रखकर इसमें अरबी डालें और एक से दो कप पानी मिला दें। इस मिश्रण को गैस पर रखकर तब तक उबालें जब तक सब्जी में उबाल ना आ जाए। उबल जाने पर सब्जी को चलाना बंद कर दें और इसमें नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला डाल दीजिए। तीन से चार मिनट तक पकने देने के बाद गैस बंद कर दें। अब एक छोटी कड़ाही में तेल गर्म करें और इसमें हींग और अजवायन डालें। इसके बाद इसमें हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल कर हल्का सा भूनें। इन सभी को अच्छे से मिला कर सब्जी में डाल कर अच्छे से मिक्स कर दें। दही अरबी तैयार है। धनिया की पत्ती से सजायें, इसे आप पूरी, पराठे के साथ सर्व करें।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 • कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम • फोन : 0361-2960054 (संपादकीय) e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, (सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)